● वर्ष-2
● अंक-276
रायपुर, मंगलवार
11 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

10 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित

गोवा की एक, पश्चिम बंगाल की छह और गुजरात की तीन सीटें शामिल

नई दिल्ली। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है। इसमें गुजरात की भी तीन सीटें शामिल हैं। यहां से मौजूदा राज्यसभा सांसद और विदेश मंत्री एस जयशंकर का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। इस चुनाव के लिए जयशंकर ने आज अपना नामांकन भर दिया है। वहीं, राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस चुनाव से दूरी बना ली है।

पिछले दिनों निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राज्यसभा की दस सीटों के लिए मतदान का एलान किया। इनके लिए मतदान 24 जुलाई को होगा। इसमें गोवा की एक, पश्चिम बंगाल की छह और गुजरात की तीन सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में डोला सेन, डेरेक ओ%ब्रायन, प्रदीप भट्टाचार्य, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रे और शांता छेत्री का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, गुजरात में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, दिनेश जेमलभाई अनावडिया और लोखंडवाला जुगल सिंह माथुरजी का कार्यकाल भी इसी तारीख को खत्म हो रहा है। गोवा में विनय तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को खत्म होने जा रहा है।

इन 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना छह जुलाई को जारी की गई है। नामांकन की अंतिम तारीख 13 जुलाई है। मतदान और मतगणना 24 को होगी।

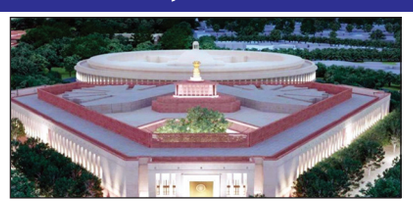

गुजरात की तीनों सीटों पर भाजपा की जीत तय है?

संख्या बल के लिहाज से भाजपा का तीनों सीट पर जीतना तय है। वहीं, गोवा में भी भाजपा के उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा है। बंगाल में सबसे ज्यादा छह सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। यहां टीएमसी ने सोमवार को ही अपने छह उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज्य में 294 विधानसभा सीटें हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 43 वोट की जरूरत होगी। अभी राज्य में टीएमसी गठबंधन के 221 विधायक हैं। ऐसे में उसके पांच उम्मीदवारों का जीतना तय माना जा रहा है। वहीं एक सीट के लिए भाजपा की दावेदारी मजबूत है। जिसके सदन में 70 विधायक हैं।

जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनमें सबसे बड़ा चेहरा विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। उन्होंने गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि, भाजपा ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन एस जयशंकर का नामांकन निश्चितथा।

विदेश मंत्री के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुजरात से राज्यसभा की सीट के लिए होने वाले चुनाव के वास्ते सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयशंकर ने संसद के उच्च सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का एक और मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, के नेतृत्व और गुजरात के लोगों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल भी जयशंकर के साथ राज्य विधानसभा परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन अधिकारी रीता मेहता को नामांकन पत्र सौंपा। जयशंकर ने कहा कि एक पड़ोसी देश ने आतंकवादी चुनौती पेश की है लेकिन सरकार इससे मजबूती से निपट रही है और मोदी सरकार देश को सुरक्षित रखेगी।नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चार साल में आए बदलावों का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला, खासकर विदेश नीति में...मैं मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में योगदान देने की उम्मीद करता हूं।

तृणमूल कांग्रेस का मुसलमानों और उत्तर बंगाल पर ध्यान

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की छह सीटों के लिए आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने

चुनाव के लिए तीन नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हुए उच्च सदन के तीन मौजूदा सांसदों – डेरेक ओ%ब्रायन (टीएमसी के राज्यसभा नेता), डोला सेन और सुखेंदु शेखर रे को फिर से नामांकित किया है। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को गुजरात, पश्चिम बंगाल और गोवा में राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। तीन राज्यों की इन 10 सीटों के लिए मतदान और मतगणना 24 जुलाई को होनी है। 10 में से छह सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले, इसके अलीपुरद्वार जिला अध्यक्ष प्रकाश चिक बड़ाईक और नागरिक समाज संगठन बांग्ला संस्कृति मंच के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम इसके नए राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। गोखले ने पार्टी की घोषणा के बाद एक ट्वीट में कहा कि मैं अपने नेताओं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने मुझे राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। मुझ पर उनके विश्वास और गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले एक युवा मध्यमवर्गीय लड़के को यह अवसर देने से मैं अभिभूत हूं। समीरुल इस्लाम पेशे से रसायन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनका मुख्य कार्य पिछड़े वर्गों को संगठित करना है। उनके संगठन ने कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए कई पहल की थी। मनिन्द्रा कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक किया।

इन दिनों

✍ नीरज कुमार दुबे

बम, बंदूक, बवाल और बंगाल

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में हिंसा की घटनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठे हैं। बंगाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की सरेआम हत्या, हिंसा, आगजनी, बमबाजी की बढ़ती घटनाएं और राज्यपाल का अपमान तथा उनके आदेशों की अवमानना की खबरें आम बात हो गयी है जोकि चिंताजनक स्थिति है। इसके अलावा, एक टीवी समाचार चैनल के स्टिंग में बंगाल में बमों के जिस कारोबार को दिखाया गया है उससे सवाल उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है? यही नहीं, विभिन्न अदालतें कई बार बंगाल में राजनीतिक हिंसा की स्थिति पर चिंता जता चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आना इस आरोप को बल प्रदान करता है कि हिंसक तत्वों को सत्ता का समर्थन प्राप्त है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान वाले दिन बंगाल में कोई बैलेट बॉक्स लेकर भागता दिखा तो किसी ने बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया तो किसी ने पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ की तो किसी ने दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं से मारपीट की। कहीं बम फटे, कहीं गोली चली और खबरों के मुताबिक इस चुनावी हिंसा में अब तक राजनीतिक दलों के 15 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। क्या यही वह शोनार बांग्ला है जिसकी कल्पना रविन्द्र नाथ टैगोर ने की थी? क्या यही वह लोकतंत्र है जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद की सबसे बढ़िया उम्मीदवार बताने वाले क्या देश को बताएंगे कि आज जो बंगाल में हो रहा है क्या ऐसी ही बम और बंदूक की संस्कृति वह पूरे देश में लाना चाहते हैं? इसके अलावा, हिंसा के इस माहौल को देखकर भी अवार्ड वापसी गैंग जिस तरह चुप्पी साधे हुए है उसको देखते हुए मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति उनका दोगलापन एक बार फिर देश के सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेन्दु अधिकारी ने अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यदि निर्वाचित सरकार से हालात नहीं संभल रहे तो लोगों को यूं ही मरने और हिंसा में घायल होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। हालिया इतिहास पर गौर करें तो यह देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के ऐलान के साथ ही शुरू होने वाला हिंसा का दौर परिणाम बाद तक जारी रहता है। राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान लगभग महीने भर जो हिंसा हुई थी उसमें पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिला। विधानसभा चुनावों के दौरान हुई राजनीतिक हिंसा में भी कई लोग मारे गये थे, किसी को जला कर मारा गया था, किसी को बम से उड़ाया गया था, किसी को फंदे पर लटकाया गया था तो किसी को अन्य निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। यही नहीं, महिलाओं के साथ दुराचार और दुर्व्यवहार हुआ था, घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया था, हालात यह हो गये थे कि बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गये थे। दुखद है कि आज भी उनमें से अधिकांश लोग न्याय की बाट जोह रहे हैं। बहरहाल, बंगाल में पंचायत चुनावों का जब ऐलान हुआ उसके बाद से राज्य में हिंसा का तांडव जारी है मगर राज्य सरकार ऑल इज वेल% के दावे पर अडिग है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बात तो लोकतंत्र की करती हैं लेकिन उनके अपने राज्य में लोकतंत्र का हाल यह है कि सैंकड़ों की संख्या में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने पंचायत चुनावों से अपने नाम वापस ले लिये क्योंकि नामांकन दाखिल करने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थीं। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव माना गया है लेकिन आज के बंगाल का सच यह है कि कोई भी चुनाव आने पर जनता के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर डर बैठ जाता है। तृणमूल कांग्रेस ने माँ, माटी और मानुष के नाम पर वोट माँगे थे इसलिए उसे मंथन करना चाहिए कि पार्टी अपने वादे पर कितनी खरी उतरी है?

हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 20 की मौत

नईदिल्ली। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आफत की बारिश लगातार जारी है। इस बारिश ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में खौफ का मंजर पैदा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जगह-जगह लगातार जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। राहत एवं बचाव का कार्य जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कई जगहों पर सैलानियों के फंसे होने की भी खबर है। सैलानियों को सुरक्षित जगह पर निकाले जाने की कोशिश हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश से उत्पन्न हुए हालात पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घर में रहने की अपील की है।

मंडी में भारी बारिश की वजह से पंचवक्त्र मंदिर पानी में डूब गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 60 साल में ऐसा किसी नहीं देखा जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। इस बार बारिश की मौसम में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। हम लोग बचाव अभियान में वर्तमान सरकार को पूरा सहयोग दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है...हमने राज्य भर में (सड़कों से मलबा हटाने के लिए) लगभग 342 मशीनें तैनात की हैं।

प्रमुख समाचार

विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी के शामिल होने की उम्मीद

नई दिल्ली। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार (10 जुलाई) को कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस महीने कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली संयुक्त विपक्ष की बैठक में

हिस्सा लेने की उम्मीद है। संयुक्त विपक्ष अपनी दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में करेगा। यह बैठक पहले 10 या 12 जुलाई को शिमला में होने वाली थी, हालांकि, शहर में खराब मौसम के कारण इसे एक नई तारीख और नए स्थल पर पुनर्निर्धारित किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि विपक्ष की अगली बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। डीके शिवकुमार ने कहा कि जैसा कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है, 17 और 18 जुलाई को (देश के) सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। तमाम नेता आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से इस बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। हमें संदेश मिला है कि वह इस बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम उन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे।

अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर

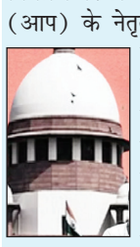

याचिका पर अपना रुख पूछा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को एक पक्ष के रूप में जोड़ने के लिए भी कहा। आप सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि ये कार्यकारी आदेश का असंवैधानिक अभ्यास था जिसने सुप्रीम कोर्ट और संविधान की मूल संरचना को ओवरराइड करने का प्रयास किया। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने के साथ ही इस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अभिषेक सिंघवी ने दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले 400 विशेषज्ञों की नियुक्ति समाप्त करने पर भी रोक लगाने की मांग की। इस पर सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया।

बिना आईडी के ही बदले जाएंगे 2000 रुपये के नोट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार के नोटों को बिना किसी रिक्विजिशन स्लिप और आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। बता दें 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। इस याचिका को अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया था और उन्होंने मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी। हालांकि, कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले कोर्ट ने बिना स्लिप और पहचान पत्र के 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट भी मांगी थी। उल्लेखनीय है कि अश्विनी उपाध्याय ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील करते हुए कहा था कि अपराधी और आतंकवादी भी 2000 रुपये के नोट बिना किसी स्लिप और पहचान पत्र के बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई करेगा, जिनमें विभिन्न राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अमित शाह से मिले राजद नेता तो भड़के नीतीश कुमार

पटना। बिहार में आज से मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इसके पहले आज बिहार विधान मंडल में महागठबंधन के बैठक हुई। इस बैठक में जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। दरअसल, बिहार

के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद एमएलसी सुनील सिंह पर बुरी तरीके से भड़क गए। बताया जा रहा है कि पूरा मामला सुनील सिंह के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर थी। सुनील सिंह ने पिछले दिनों अमित शाह से मुलाकात की थी और उस फोटो को साझा किया था। इसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने सुनील सिंह से इस पर जवाब मांगा। मामला बढ़ता देख बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को बीच-बचाव करना पड़ा। हालांकि बताया जा रहा है कि तीखी नोकझोंक के दौरान आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने भी नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं राजनीति में पिछले 27 वर्षों से हूं और मैं जहां खड़ा हूं, उसी जगह पर आज भी मौजूद हूं।

मोदी की यात्रा में अब नेवी को भी मिलेगी फ्रांस से 26 राफेल

नईदिल्ली। भारत फ्रांस से 26 राफेल एम नौसैनिक जेट और तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियां खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर कर सकता है। इन सौदों की घोषणा 14 से 16 जुलाई के बीच होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान होने की उम्मीद है। रक्षा खरीद बोर्ड (डीपीपी) ने सोमवार को सौदों को मंजूरी दे दी। लगभग 90,000 करोड़ रुपये के सौदे में 26 राफेल एम विमान शामिल होंगे, जिसमें 22 सिंगल-सीटर और चार डबल-सीटर ट्रेनर संस्करण होंगे। शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक, तीन अतिरिक्त पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पीन सौदे का हिस्सा होंगी। राफेल विमान भारतीय नौसेना के विमान वाहक पर तैनाती के लिए हैं और इस सप्ताह रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने की संभावना है। भारतीय नौसेना हाल के वर्षों में विमानों और पनडुब्बियों की कमी का सामना कर रही है, जिससे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। इन विमानों का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर किया जाएगा, जो वर्तमान में मिग -29 का उपयोग करते हैं। फ्रांस में आधिकारिक घोषणा से पहले अगले कुछ दिनों में सौदों को रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

समान नागरिक संहिता से हो रही अनुच्छेद 371 की चचा

समान नागरिक संहिता से ज्यादा हो रही अनुच्छेद 371 की चर्चा

नईदिल्ली। समान नागरिक संहिता का मुद्दा बहस में आते ही इसके विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं। यूसीसी को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में जबरदस्त हलचल है। वहीं आदिवासी समुदाय में भी इसको लेकर रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर देश के पूर्वोत्तर हिस्से और आदिवासी समाज में यूसीसी पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और उन्हें किस बात का डर सता रहा है।

पूर्वोत्तर को किस बात का सता रहा डर?

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 220 से अधिक विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं और इसे दुनिया के सांस्कृतिक रूप से सबसे विविध क्षेत्र में से एक माना जाता है। पूर्वोत्तर में जनजातीय समूहों को भारत के संविधान के तहत प्रथाओं के साथ चले आ रहे कानूनों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनजातीय आबादी 94.4 प्रतिशत है, जबकि नगालैंड और मेघालय में क्रमशः 86.5 और 86.1 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर के प्रमुख आदिवासी समूहों को चिंता है कि एक समान नागरिक संहिता के आने से लंबे समय से चले आ रहे रीति-रिवाजों और प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसे संविधान से संरक्षण मिला हुआ है।

धारा 371 क्यों चर्चा में आया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले नागा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से आश्वासन का दावा किया है कि विधि आयोग राज्य में ईसाई समुदाय और कुछ आदिवासियों को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून से बाहर करने के विचार पर विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में 12 सदस्यीय नागा प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को शाह से मुलाकात की और यूसीसी के कार्यान्वयन और नागालैंड शांति वार्ता में प्रगति की कमी सहित राज्य की विभिन्न चिंताओं के बारे में बात की। हमने गृह मंत्री को अनुच्छेद 371 (ए) से अवगत कराया, जो नागालैंड पर लागू है और जुलाई

1960 में नागा जनजातियों और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 16 सूत्री समझौते पर आधारित है। इस समझौते के अनुसार, साथ ही अनुच्छेद 371 (ए), हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में जिस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, उसे संसद द्वारा पारित किसी भी केंद्रीय कानून द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है।

आदिवासी क्यों कर रहे विरोध?

आदिवासी समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आने से खत्म हो सकती है। मसलन, एक पुरुष एक साथ कई महिलाओं से शादी कर सकता है या एक महिला कई पुरुषों से शादी कर सकती है। असम, बिहार और ओडिशा में कुछ जनजातियां उत्तराधिकार के परंपरागत कानूनों का पालन करती है। इन जनजातियों में असम की खासिया और जैतिया हिल्स के कूर्ग ईसाई, खासिया और ज्येंतेंग शामिल हैं। साथ ही बिहार और ओडिशा की मुंडा और ओरांव जनजातियां भी इसमें आती है।

झारखंड और छत्तीसगढ़ में विरोध

जैसे-जैसे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर बहस चल रही है, झारखंड, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय बड़े पैमाने पर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज (सीएसएएस) ने यूसीसी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे प्रथागत कानूनों का पालन करने वाले आदिवासियों की पहचान और पारंपरिक प्रथाओं को खतरा हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीएसएएस अध्यक्ष अरविंद नेताम ने कहा कि उनका संगठन समान नागरिक संहिता का पूरी तरह से विरोध नहीं करता है, लेकिन केंद्र को इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सभी को विश्वास में लेना चाहिए। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने 08 जुलाई को रांची में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. आदिवासी संगठन के सदस्यों ने रांची में भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आदिवासी संगठन के नेता अजय तिर्की ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वे आदिवासी समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा नागरिकों के लिए समान कानून पर जोर देने के बाद यूसीसी पर हंगामा शुरू हो गया है। विशेष रूप से, 14 जून को, विधि आयोग ने हितधारकों से विचार मांगकर यूसीसी पर एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की।

विपक्ष के विमर्श का रुख ही मोड़ दिया

सीएए और एनआरसी के हश्र को मोदी सरकार पहले ही देख चुकी है। ऐसे में भले ही पीएम मोदी ने साफ शब्दों में वकालत की है। लेकिन ये कब और कैसे लागू होगा, इसको लेकर चर्चा विमर्श जारी है। सरकार ये संकेत दे चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले वो व्यापक विचार-विमर्श करना चाहती है और पूरे देश में लागू करने से पहले किसी एक राज्य को मॉडल के रूप में पेश करना चाहती है। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में मोदी विरोधी मोर्चा का महाजुटान हुआ था और बैठक में सभी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर सहमति भी बनती दिखी थी। लेकिन मुद्दा और पीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकार है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों से पहले प्रधानमंत्री ने यूसीसी का सिक्का उछाल दिया है। अब विपक्ष प्रो एक्टिव होने की बजाए रिएक्टिव हो गया है।

सर्व हिंदू समाज व सनातन संघर्ष समिति की अगुवाई में किया धरना प्रदर्शन

■ गौ-हत्या व गौ-मांस बिक्री का मामला

कोरबा। गौ- हत्या व गौ-मांस बिक्री का मामला सामने आने के बाद सर्व हिंदू समाज व सनातन संघर्ष समिति की अगुवाई में प्रतिकार करते हुए धरना. प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि शांतिप्रिय क्षेत्र कोरबा में इस तरह की गतिविधियां पहले कभी नहीं रही, अचानक गौ-हत्या और गौ. मांस की बिक्री करने का साहस भला कैसे जुटा लिया गया। जिस छत्तीसगढ़ में सरकार गौ संवर्धन और संरक्षण के दावे करते नहीं थक रही है, आखिर वहां इस तरह की घटनाओं से क्या संदेश जाता है। उन्होंने आशंका व्यक्त किया कि छोटे व्यक्ति की आड़ लेकर कोई बड़ा गिरोह इस तरह के घृणास्पद खेल में शामिल है। इस मामले की बारीकी से जांच कराई जाए और गिरोह में शामिल दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे निहारिका के समीप आयोजित धरना में युवाओं, पुरुषों और मातृशक्ति की काफी संख्या में उपस्थिति रही। सबसे पहले सभी समाज व संगठन प्रमुखों ने गौ-माता को तिलक, वस्त्र से पूजा अेर्चना किया गया। पिछले मोतीसागरपारा और इमलीडुग्गू क्षेत्र में हुई घटना को लेकर नाराज लोगों ने

हैरानी जताई कि आखिर इस मामले में दोषियों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान गौ हत्या बंद हो और गौ हत्यारों पर कठोर कार्रवाई करो, के नारे भी लगाए गए। धरना के शुरुआत में विषय की प्रस्तावना पढ़ी गई और कोरबा के ज्वलंत विषय की तरफ आम नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया गया। उपस्थितजनों को बताया गया कि जो हिंदू समाज गौमाता के प्रति विशेष सम्मान और आदर भाव रखता है। उसका आखिर क्या हश्र हो रहा है। यह सब हमें भीतर से उद्वेलित करता है और आगे कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित भी करता है। हिंदू समाज कि 35 से ज्यादा इकाइयों और भारत के आत्मतत्व को निष्ठा के साथ व्यवहार में शामिल करने वाले सामाजिक संगठनों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में जनमानस को जागृत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मोती सागरपारा और इमली डुग्गू क्षेत्र में हुई घटना हैरान करने वाली है। हिंदू जनसंख्या वाले क्षेत्र में आखिर कोई व्यक्ति इस तरह का अत्यंत समाज विरोधी और घृणित कार्य कैसे कर सकता है। वक्ताओं ने हैरानी जताई कि आखिर मूल व्यवसाय की आड़ में कोई व्यक्ति गौ मांस की बिक्री व्यापक पैमाने पर करने के लिए भारी.भरकम संसाधन तब कैसे कर सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो। मौके पर डीप फ्रीजर की उपस्थिति और उसमें बड़ी मात्रा में गौ मांस का रखा होना कई प्रकार के सवालों को जन्म देता है। दूसरी तरफ इसी व्यवसाय के लिए गोडाउन बनाना और वहां गाय के अवशेष रखे जाने से कई सवाल खड़े हो जाते हैं।

सर्व हिंदू समाज और संगठन प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम का सौंपे ज्ञापन में गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताते कहा कि प्रकरण में दोषियों पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। साथ यह भी कहा कि जिले के वनांचल क्षेत्र से रात में काफी संख्या में गौ तस्करी की जाती हैए पर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मामलों में पुलिस थाना स्तर पर स्वयं से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि पुलिस को घटना की जानकारी रहती है। गौ. हत्या और गौ तस्करी के षड्यंत्र के पीछे जो भी असामाजिक तत्व शामिल है उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

प्रशासन की ओर से आंदोलन स्थल पर तहसीलदार मुकेश देवांगन भी उपस्थित रहे। धरना समाप्त होने के बाद समाज के प्रबुद्धजनों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रशासन से मांग कि गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री की रोकथाम करने के लिए जिले की सभी तहसील विकासखंड और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी गोवंश की हत्या तथा गौ तस्करी निषेध सूचनाएं प्रसारित कराई जाए। इसके साथ ही इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर होने वाले दंड प्रविधान का प्रचार प्रसार व ग्रामीण क्षेत्र में मुनादी कराने की व्यवस्था कराई जाए।

इस मौके पर मुकेश गोयल अग्रेसन गौशाला, गीता यादव सर्व यादव समाज, रश्मि शर्मा ब्राह्माण समाज, अरुण दास वैष्णव वैष्णव विकास समाज, गायत्री नायर, विभा गौराहा आर्य समाज, कमलेश मिश्रा गायत्री परिवार, हेमंत महूलिकर महाराष्ट्र मंडल, भोजराम देवांगन धर्म जागरण, संजू देवी राजपूत राजपूत क्षत्रिय समाज, भागवत साहू साहू समाज, आशीष खेतान सीए एसोसिएशन, लालिमा जायसवाल रामकृष्ण गौसेवा समिति बाल्को, सुनील जैन अग्रेसन गौसेवा समिति, कृष्ण कुमार श्रीवास श्रीवास समाज, नाथू राम यादव सर्व यादव समाज, अशोक तिवारी, बजरंग अग्रवाल इंदरा विहार समिति, योगेश जैन चैंबर आफ कामर्स, राधेश्याम अग्रवाल, छन्नू सिंह, विनय राय पूर्वांचल विकास समिति, अजय दुबे सनातन संघर्ष समिति, सभी समाज प्रमुख, संगठन प्रमुखों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन कैलाश नाहक व आभार प्रदर्शन चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने किया।

हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति हमारी सरकार की प्राथमिकता : रेखचंद जैन

जगदलपुर। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कलचा उपनपाल करनपुर क्षेत्र के 6 ग्रामों में 2 करोड़ 18 लाख 12 हजार रुपए की लागत से सिंगल विलेज नल-जल योजना का भूमि-पूजन किया

जिन ग्रामों में भूमिपूजन किया गया उनमें ग्राम कलचा,कुम्हरावण्ड ,रामपाल,भालूगुडा, करनपुर,बीजापुट में सिंगल विलेज नल-जल योजना का भूमि-पूजन किया गया जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी

ग्राम पंचायत कलचा में 58.97 लाख रुपए की लागत से 1 नग पम्प हाउस, क्लोरिनेशन कक्ष 1 नग, बाउंड्री वॉल 1 नग,पाईप लाईन विस्तार कार्य 905 मीटर जिससे की 423 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी,ग्राम पंचायत कलचा के आश्रित ग्राम कुम्हरावण्ड में 46.11 लाख रुपए की लागत से क्लोरिनेशन कक्ष 1 नग, बाउंड्री वॉल 1 नग, टंकी निर्माण 40 किलो लीटर, पाइप लाइन बिछाने का कार्य 893 मीटर जिससे 105 घरों तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी,ग्राम पंचायत करनपुर के आश्रित ग्राम रामपाल में 27.45 लाख रुपए की लागत से सोलर पंप 1 नग 6 मीटर स्टेजिंग,10000 लीटर टंकी, पाइप लाइन बिछाने का कार्य 960 मीटर जिससे की 99 घरों तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति

सुनिश्चित हो सकेगी, ग्राम पंचायत करनपुर में 34.50 लाख रुपए की लागत से पम्प हाउस 1 नग, क्लोरिनेशन कक्ष 1 नग, पाइप लाइन बिछाने का कार्य 408 मीटर जिससे की 272 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, आश्रित ग्राम भालुगुडा में 8 लाख रुपए की लागत से 931 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य जिससे 30 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, ग्राम पंचायत उपनपाल के आश्रित ग्राम बीजापुट में 43.09 लाख रुपए की लागत से पावर पंप 1 नग 3 एच पी , क्लोरिनेशन कक्ष 1 नग, बाउंड्री वॉल 1 नग, टंकी निर्माण 40 किलो लीटर, पाइप लाइन बिछाने का कार्य 475 मीटर जिससे की 125 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा अनुरूप शुद्ध पेयजल आपूर्ति हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और हर ग्राम पंचायत के हर ग्राम के हर पारा मोहल्ले के हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है जल ही जीवन है इस मूलमंत्र के साथ हमारी सरकार नल जल योजना के क्रियान्वयन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है उन्होंने कहा की जो सुविधाएं पहले शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध थी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो सकेगा जिससे हर घर को नल से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ सरपंच कलचा कमल नाग, सरपंच करनपुर त्रिपती नागेश, सरपंच उपनपाल कामिनी नागेश, सरपंच संघ के संभागीय अध्यक्ष लैखन बघेल, वरिष्ठ नेता रमेश पात्रो, संतोष सिंह, अवधेश झा,संजय कुमार नाग समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

लाखों रुपए का स्कूली बच्चों का गणवेश फेंक दिया गया

बीजापुर। कलेक्टर कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर डारापारा आंगनबाड़ी केंद्र के समीप बने सामुदायिक भवन में सिलाई कर कपड़े रखे गए थे, जिसे भवन से बाहर फेंक दिया गया, ताकि उस भवन पर राशन दुकान संचालित हो सके। शिक्षा विभाग ने लाखों रुपए के स्कूली बच्चों का गणवेश कैसे कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, यह जांच का विषय है। शासकीय स्कूलों में पढने वाले आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था के साथ-साथ कपड़े, जूते, पुस्तक और खाने पीने की समुचित व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से की जाती है। आदिवासी बच्चों के लिए प्रति वर्ष गणवेश एवं अन्य सामग्री हेतु करोड़ों रूपये जिला प्रशासन को आबंटित की जाती है, जिसमें जिले भर के कन्या आश्रम और बालक आश्रम के बच्चों को गणवेश की सिलाई हेतु थान कपड़ा क्रय कर महिला स्व सहायता समूह को सौंपा जाता है। सामुदायिक भवन में सिलाई कर रखे गये कपड़े को सुरक्षित रखे जाने की सुचित व्यवस्था नही कर लापरवाही के चलते लाखों रुपए के स्कूली बच्चों का गणवेश अब कचरे का ढेर में परिवर्तित हो गया, जिसे बाहर फेंक दिया गया। उल्लेखनिय है कि लगभग एक वर्ष पूर्व आश्रम अधीक्षओं से स्कूली बच्चों के गणवेश क्रय करने के लिए आश्रमों के एक माह का लगभग 50 हजार रूपए शिष्यवृत्ति की रकम ली गई थी।

छत्तीसगढ़ सरकार की पहल, हरेली पर सी-मार्ट से गेड़ी खरीद सकेंगे लोग

बालोद। छत्तीसगढ़ी संस्कृति का पहला त्योहार हरेली आने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में जिस तरह से छत्तीसगढ़ी त्योहारों को तवज्जो दी गई उसका अब परिणाम यह दिखने लगा है कि बालोद शहर के हाईटेक सी-मार्ट में पारंपरिक गेड़ी बिकने लगी है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप बालोद जिले के सी-मार्ट में इस बार हरेली तिहार हेतु आम-नागरिकों के लिए गेड़ी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया है।

बता दें कि हरेली त्योहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। त्योहार के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है, परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते हैं। गेड़ी चढ़कर ग्रामीण-जन और कृषक-समाज वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। वर्षा ऋतु के दौरान गांवों में सभी तरफ कीचड़ होता है, लेकिन गेड़ी चढ़कर कहीं भी आसानी से आया-जाया जा सकता है।

बांस से बनाई जाती है गेड़ियां

गेड़ियां बांस से बनाई जाती हैं। दो बांस में बराबरी दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाड़कर उसे दो भागों में बांटा जाता है, उसे रस्सी से फिर से जोड़कर दो पउवा बनाया जाता है। यह पउवा असल में पैरदान होता है, जिसे लंबाई में पहले काटे गए दो बांसों में लगाई गई कीलों के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती है, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है।

जानिए गेड़ी का एक पक्ष

बालोद कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि हरेली के पर्व में गेड़ी का अपना अलग महत्व है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में हरेली पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं उन्होंने आगे बताया कि गेड़ी के पीछे एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका प्रचलन वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा के कारण गांव के अनेक जगह कीचड़ भर जाता है, इस समय गेड़ी पर बच्चे चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं उसमें कीचड़ लग जाने का भय नहीं होता। बच्चे गेड़ी के सहारे कहीं से भी आ जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नक्सल प्रभावित सोनपुर में सुरक्षा बलों की निगरानी में विकास कार्य

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की निगरानी में विकास कार्य कराये जा रहे हैं। एक ऐसे ही डेवलपमेंट वर्क की तस्वीर नारायणपुर के सोनपुर इलाके में सामने आई है। जहां सुरक्षा बलों की निगरानी में विकास कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। जिसके चलते सालों से यहां विकास के काम अटके पड़े हैं। अक्सर यहां नक्सली अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए कई छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। कई बार नक्सली सड़क निर्माण या विकास कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर चुके हैं। इन घटनाओं में की लोगों की जान भी जा चुकी है। सड़क या पुल निर्माण के दौरान नक्सलियों के हमले का डर बना रहता है। बावजूद इसके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की बयान बहाने सुरक्षाबल भी डटे हुए हैं और अपनी निगरानी में पुल और सड़क निर्माण का काम करा रहे हैं।

25 से अधिक महिलाओं ने किया भाजपा प्रवेश

कोरबा। आज पूरे देश में मोदी लहर चल रही है भाजपा के विकास कार्यो को देखकर बड़ी संख्या में लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं साथ ही पार्टीयां अपने-अपने समर्थकों को पार्टी में प्रवेश कर आ रहे हैं। इसी कड़ी में दमाद मोहल्ला दादरखुर्द में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वैशाली रत्न पाखी के समक्ष में 25 से अधिक संख्या में महिलाओं ने भाजपा में प्रवेश किया। जिसमें बृहस्पति यादव ने सराहनीय कार्य कर सभी को भाजपा के गमछा पहनाकर भाजपा प्रवेश कराया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के बृजेश यादव , कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष स्वाति कश्यप, मंडल महामंत्री पुष्पकला साहू भी मौजूद रही।

डूब गया एनएच-43, खेतों में जमा हुआ मुसीबत का मुरूम

कोरिया। जिले में कल रात से लगातार हो रही बारिश से कटनी गुमला नेशनल हाइवे-43 पर बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन के समीप सड़क पर भारी जल जमाव हो गया है. जिससे लोगों को आने-जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे स्टेशन का मेन गेट कीचड़ में तब्दील हो चुका है. रविवार की रात हुई बारिश में लगभग 500 मीटर सड़क पानी में डूब गई. साथ ही आसपास के इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। दरअसल, बैकुंठपुर रोड़ रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन और सामने ही रेलवे आवास बनाने के लिए रेलवे ने हाइवे किनारे लगभग 5 फ्रि मिट्टी पाट दी है. साथ ही पुलिया के पास पानी निकासी के लिए बने नाले में भी मुरूम मिट्टी डालकर जाम कर दिया है. रेलवे प्रबंधन और ठेकेदार की अदूरदर्शिता की लापरवाही से हाइवे की सड़क नाले में तब्दील हो चुकी है और घरों में बारिश का पानी भर रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि, पानी के बहाव के साथ मिट्टी और मुरूम उनके खेतों में जमा हो रहा है, जिससे उन्हें खेती किसानी के काम में दिक्कत हो रही है।

दुर्ग के सरकारी गोदाम से चावल और शक्कर ले गए चोर

दुर्ग। अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय राशन की गोदाम में चोरी का मामला सामने आया है। शासकीय राशन की गोदाम से 96 क्विंटल चावल और 75 किलो शक्कर की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि 4 लाख 45 हजार कीमत का राशन चोरी हुआ है। ये ग्राम पंचायत आमटी स्थित सोसायटी है, जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोदाम के लोहे के शटर एवं चैनल गेट को तोड़कर तथा अंदर प्रवेश कर चोरी कर ले गया है। मामले पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी अंडा पुलिस ने जल्द से जल्द अज्ञात आरोपी को पकड़े जाने का भरोसा दिलाया है। मिली जानकारी के मुताबिक अंडा क्षेत्र अंतर्गत 5 किमी. की दूरी पर ग्राम आमटी के सार्वजनिक वितरण प्रणाली गोदाम में रखे चावल व शक्कर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। सोसायटी संचालक जामवंत देशमुख पिता सोनराम देशमुख 57 वर्ष पता ग्राम सलौनी तिलखेरी थाना अर्जुन्दा जिला बालोद ने थाना प्रभारी अण्डा अम्बिकाप्रसाद ध्रुव से लिखित शिकायत किया है।

बीएसपी आवास के लीजधारी करा सकते हैं रजिस्ट्री

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप में लीज पर आवास लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर टाउनशिप के आवास लीज पर लेने वाले लोगों का 21 साल से लीज की रजिस्ट्री के लिए जारी इंतजार खत्म हो गया है। बीएसपी टाउनशिप में लीज पर आवास लेकर निवास करने वालों के लिए लीज की रजिस्ट्री का मार्ग खुल गया है। इसके साथ ही बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले लीज धारक अपने आवासों के लीज की रजिस्ट्री करा सकते हैं। जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि भिलाई स्टील प्लांट द्वारा सेल के घाटे के दौरान टाउनशिप के आवासों को लीज पर देना शुरू किया गया था। 5 चरणों में करीब साढ़े 4 हजार आवास 30 साल के लिए लीज पर दिए गए। बीएसपी प्रबंधन से आवास लीज पर मिलने के बाद लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इन आवासों का नवीनीकरण भी कर लिया। लोगों को आवास तो मिल गया लेकिन उनकी लीज की रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी।

भोरमदेव मंदिर में उमड़ी शिवभक्तों की भीड़, सावन सोमवार के पहले दिन की विशेष पूजा

कवर्धा। सावन सोमवार के पहले दिन भोरमदेव में श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा अर्चना में लीन दिखे।हर-हर महादेव और बम भोले के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठा। बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक श्रद्धालु 18 किलोमीटर की पदयात्रा करके आए। इस दौरान एसपी, कलेक्टर समेत सैंकड़ों श्रद्धालुओं ने शिव की विशेष पूजा अर्चना की।

हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव की पूजा से आपको मन चाहा फल मिल सकता है। इसलिए सावन माह में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोग भगवान भोले नाथ को प्रसन्न करने के लिए नंगे पांव कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना कष्ट

उठाकर भोलेनाथ के दर्शन करेगा उसकी मनोकामना उतनी ही जल्दी पूरी होगी।

छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर 11वीं सदी के नागवंशी राजाओं ने बनाया था। पुरातनकाल से ही ये मंदिर लोगों के बीच आस्था का केंद्र है।यह मंदिर भगवान शिव और भगवान गणेश की छवियों के अलावा, भगवान विष्णु के दस अवतारों की छवियों को भी चित्रित करता है। भोरमदेव मंदिर नागर शैली और जटिल नक्काशीदार चित्र कला का एक शानदार नमूना है।श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।

जिला प्रशासन ने इस बार मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोगों के लिए खास व्यवस्था की है। जिसमें बाहर से आने वाले कावंड़िएं और श्रद्धालु मंदिर के पास ही रुक सकते हैं।उनके खानपान की व्यवस्था जिला प्रशासन ने करवाई है।साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और यातायात की टीम मौजूद है।

शिवालयों में गूंजा हर-हर शंभू, हनुमानगढ़ी और कनकी शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सावन मास के पहले सोमवार को शिवालय बोलबम के नारों से गूंज उठे। महादेव को जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जिले के उपनगरीय क्षेत्र कटघोरा में हनुमान गढ़ी के शिवमंदिर और कनकी शिव मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही उमड़ पड़े। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुजारी शिवम उपाध्याय ने बताया कि कई सालों बाद ऐसा संजोग बना है, जो सावन मास इस वर्ष 2 माह तक रहेगा और विशेष पूजा-अर्चना होगी। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना और भक्ति का विशेष महत्व है। इसे लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह रहता है। कटघोरा के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी के शिव मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। रिमझिम फुहारों के बीच शिव के भक्त दिनभर भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना लेकर दुग्ध अभिषेक, जलाभिषेक, बिल्वपत्र, पुष्प, सोम पत्र श्रीफल, भांग, धतूरा, कनेर, भस्म सहित शिव को प्रिय लगने वाली वस्तुओं के साथ अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन मास के साथ ही शिव मंदिर में शिवभक्त कावड़ियों अहिरन नदी व नरसिंह गंगा से जल लेकर आने-जाने से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। वहीं कोरबा से 25 किमी दूर कनकी शिव मंदिर में भी रविवार रात से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा था। सर्वमंगला मंदिर से जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु हसदेव नदी से जल लेकर कनकी शिव मंदिर के लिए निकल पड़े।

खाद्य व औषधि प्रशासन ने 9 दुकानों को जारी किया नोटिस

जगदलपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा बरसाती मौसम एवं त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त चौपाटी फूड स्टालों, किराना दुकानों, होटल में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही किया गया। निरीक्षण के दौरान जिन खाद्य परिसरों में नियमानुसार स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं करना पाया गया उन्हें तत्काल सुधार करने हेतु 9 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान एक्सपायर खाद्य सामग्रीयों को नष्ट करते हुए भविष्य में नियम का पालन नही करने पर चालानी कार्यवाही करने संबंधी चेतावनी दी गयी। इस दौरान तोकापाल ब्लॉक के समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों एवं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के सामने संचालित फूड स्टालों, किराना दुकान एवं होटलों का सघन निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं टीम द्वारा किया गया। खाद्य लाइसेंस की जांच की गई, जिसमें बहुत से प्रतिष्ठानों में लाइसेंस नहीं पाया गया, उन्हें सात दिवस का समय देते खाद्य लाइसेंस-पंजीयन लेकर ही खाद्य कारोबार करने हेतु निर्देशित किया गया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

जयशंकर ने गांधीनगर में दाखिल किया नामांकन

नईदिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार (10 जुलाई) को गुजरात के गांधीनगर से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात की जनता और विधायकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह आने वाले 4 सालों में होने वाली प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे। चुनाव आवश्यक हो गया था क्योंकि जयशंकर का कार्यकाल 18 अगस्त को गुजरात के दो अन्य राज्यसभा सदस्यों जुगलसिंह लोखंडवाला और दिनेश अनावाडिया के साथ समाप्त हो जाएगा। एस जयशंकर ने नामांकन दाखिल करने के बात कहा कि अपना सबसे पहले मैं पीएम मोदी, बीजेपी नेतृत्व और गुजरात की जनता और विधायकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चार साल पहले मुझे राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला था। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलावों का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला।

सत्येंद्र जैन की जमानत 24 तक सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को मेडिकल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

तमिलनाडु के राज्यपाल की बर्खास्तगी की स्टालिन की मांग उचित : सिब्बल

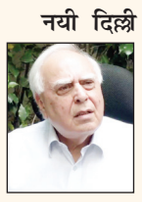

नयी दिल्ली। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की राज्यपाल आर एन रवि की बर्खास्तगी की मांग का समर्थन करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्यों के राज्यपाल 'अस्थिरता पैदा करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं'। स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि रवि 'साम्प्रदायिक घृणा को भड़काते हैं' और तमिलनाडु की शांति के लिए 'खतरा' हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा, 'राज्यपाल के व्यवहार और कदम ने साबित किया है कि वह पक्षपात कर रहे हैं और राज्यपाल के पद पर रहने के लायक नहीं है। रवि को शीर्ष पद से हटाया जाना चाहिए है।' सिब्बल ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''(भीम राव) आंबेडकर ने राज्यपालों को लेकर कहा था कि यह केवल एक नामपात्र का पद है. उसे प्रशासन में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।'

शिक्षक भर्ती मामले में अभिषेक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी की संलिप्तता की जांच करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता एचसी के आदेश में हस्तक्षेप करना इस स्तर पर जांच को दबाने जैसा होगा। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकता है। पिछले महीने, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्राथमिक विद्यालय की नौकरियों से जुड़े घोटाले की चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को बुलाया था। टीएमसी महासचिव ने राजनीतिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए ईडी के समन का पालन करने से इनकार कर दिया था।

शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह पर 31 को सुको में सुनवाई

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गयी है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 'शिवसेना' नाम और पार्टी का चिह्न 'धनुष और बाण' राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जताई है। हम आपको बता दें कि वकील अमित आनंद तिवारी ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि मामले को 31 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। पीठ ने वकील अमित आनंद तिवारी को शिंदे धड़े द्वारा दायर जवाब का प्रत्युत्तर देने की अनुमति देते हुए कहा, ''इसे 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। हम इस पर उसी दिन सुनवाई करेंगे।''

मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राहुल पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष बोले-

प्रजातंत्र नहीं, राहुल की नेतागिरी खतरे में हैं : नड्डा

गोधरा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक राजनीति करती रही, गरीबों के नाम पर वोट लिया और गरीबों को ही लूटती रही। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। जेपी नड्डा गुजरात के गोधरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें नंबर पर थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले 92% मोबाइल विदेशों से बनकर आता था और सबसे ज्यादा चीन से आता था, आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है। उन्होंने कहा कि स्टील उत्पादन में भारत चौथे नंबर पर था, आज भारत स्टील उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं। वह पता नहीं कौन सा पंजा था जिसमें वह 85 पैसे चिपक जाते थे। आज के डिजिटल इंडिया में पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है। उन्होंने कहा कि 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी के 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने। जिसमें से 8 एयरपोर्ट तो हमारे गुजरात में ही बन रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर बोल रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। ये बातें वह कर रहा है जिनकी दादी ने आपातकाल लगाकार लाखों लोगों को जेल भेज दिया था। ऐसे लोग प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में प्रजातंत्र तो खतरे में नहीं है बल्कि इनकी नेतागिरी खतरे मे हैं। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष के अंदर मोदी जी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। वंशवाद और वोट बैंक की राजनीति से निकालकर देश को विकासवाद की ओर ले गए हैं। 1951-52 से हम सोचते रहे कि अंत्योदय, एकात्म मानववाद, गरीब का भला हो, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो।

राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं, बल्कि चला रहे नफरत का मेगा मॉल

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल मोहब्बत की दुकान नहीं, बल्कि नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवार-केंद्रित दलों में बदलने का भी आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि उन्हें लोगों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है। वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने में लगे हैं। नड्डा ने आगे कहा कि जब भी पीएम मोदी को वैश्विक मंच पर सराहना मिलती है तो कांग्रेस के लोग परेशान हो जाते हैं। पीएम का विरोध करने की कोशिश करते-करते कांग्रेस नेताओं ने देश का विरोध करना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस नेताओं पर निचले स्तर की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परेशान हैं, क्योंकि पीएम मोदी भारत के 140 करोड़ नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा कैसे करते हैं जबकि आप लगातार देश के पीएम के लिए नफरत फैला रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप वास्तव में नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं।

भाजपा नेता ने दावा किया कि जहां पीएम मोदी लोगों की सेवा करने में व्यस्त हैं, वहीं विपक्षी दल अपने परिवार को बचाने में व्यस्त हैं। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, केसीआर की पार्टी (भारत राष्ट्र समिति), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के साथ-साथ चौटाला और बादल परिवारों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि ये राजनीतिक दल केवल परिवारों के बारे में चिंतित हैं। नड्डा ने कहा कि ये राजनीतिक दल अपने परिवारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें आपकी चिंता नहीं है। दूसरी तरफ, मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब एक परिवार-उन्मुख पार्टी बनकर रह गई है।

जेपी नड्डा ने एक दूसरे पर निशाना साधने से बचने की दी सलाह

नईदिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के तेलंगाना नेताओं को अनुशासनहीनता के खिलाफ चेतावनी दी है। रविवार रात पार्टी नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने उनसे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, नड्डा ने हाल के दिनों में कुछ नेताओं के बयानों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इन बयानों से पार्टी को नुकसान हुआ। रविवार को 11 राज्यों के पार्टी अध्यक्षों और संगठन सचिवों के साथ बैठक के बाद, नड्डा ने शहर के एक होटल में तेलंगाना नेताओं से मुलाकात की। उनके साथ अलग-अलग बैठकों के दौरान, उन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलते समय सतर्क रहने का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि पार्टी लाइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के बयानों और मीडिया लीक से पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। नड्डा ने नेताओं से कहा कि उन्हें इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मिलकर काम करते हुए अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने उन्हें एक दूसरे पर निशाना साधने से बचने की सलाह दी। भाजपा प्रमुख ने स्पष्ट किया कि सभी नेताओं को सब कुछ एक तरफ रखकर पार्टी को सत्ता में लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

फारुख अबदुल्ला हो या गुलाम नबी आजाद

यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे जम्मू-कश्मीर के नेता

नईदिल्ली। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। भाजपा की ओर से इस पर लगातार आगे बढ़ने के बाद की जा रही है। तो वहीं विपक्ष के कई दल इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब विधि आयोग ने इसको लेकर धार्मिक संगठनों और आम लोगों से सुझाव मांगे थे। हालांकि, यह मामला गर्म तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में इसकी चर्चा कर दी। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार के पास कोई उपलब्धियां बताने के लिए नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता को इस्लाम विरोधी बताया जा रहा है।

जबसे यूसीसी की चर्चा शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े राजनेता यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले पर कहा कि केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह विविधताओं से भरा देश हैं और यहां विभिन्न जातियों व धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरिया कानून है। उन्होंने कहा कि केंद्र को इसे आगे बढ़ाने के बजाय इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि तूफान आ जाए। यूसीसी के मुद्दे पर मीडिया कर्मियों के पूछे गए एक सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने का इरादा रखती है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत पर चल रही है और हम ष्ट्र का ड्राफ्ट आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे।

समान नागरिक संहिता से जुड़े एक सवाल पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे किस एकरूपता की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास पहले से ही समान आपराधिक संहिता है और वह पूरी तरह से काम कर रही है। पीडीपी अध्यक्ष ने भाजपा पर उसके दोहरे मानदंड के लिए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वे यूसीसी के बारे में बात करते हैं लेकिन पहले बलात्कार विरोधी कानून लागू करे। वे बलात्कारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। जबकि बिलकिस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, महिला पहलवानों का बलात्कारी आज़ाद घूम रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यूसीसी को लागू करने का सवाल ही नहीं है। यह अनुच्छेद-370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। सभी धर्म इसमें शामिल हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी, इन सभी लोगों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा।

जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुस्लिम आबादी बाकी के समुदायों से ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 69% इस्लाम को मानने वाले जम्मू कश्मीर में रहते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले 28.80% और सिख धर्म को मानने वाले लगभग 2ब लोग जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। जम्मू कश्मीर की ज्यादातर सीटे उत्तरी कश्मीर से हुआ करती हैं। उत्तरी कश्मीर में मुसलमानों का बोलबाला है। इसका असर चुनाव पर भी रहता है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के राजनेता जबरदस्त तरीके से यूसीसी का विरोध करते रहे।

खेल
प्रमुख समाचार

पार्थ सालुंखे रिकर्व वर्ग में युवा विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने

लिमरिक। पार्थ सालुंखे युवा विश्व चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने, जिससे भारत ने अपने अभियान को 11 पदकों के साथ समाप्त किया। युवा विश्व चैम्पियनशिप में यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने रविवार को यहां अंडर-21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरिया के तीरंदाज को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। रैंकिंग राउंड में शीर्ष पर रहने वाले सालुंखे ने सातवीं वरीयता प्राप्त सोंग इंजुन को पांच सेट के कड़े मुकाबले में 7-3 (26-26, 25-28, 28-26, 29-26, 28-26) से हराया।

भारत ने अंडर-21 महिला रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में भी कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक मुकाबले में भाजा कौर ने चीनी ताइपे की सु सीन-यू को 7-1 (28-25, 27-27, 29-25, 30-26) से हराया। भारत का अभियान छह स्वर्ण, एक रजत और चार कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ, जो कुल पदकों की संख्या के मामले में सर्वोच्च था। टीम हालांकि रैंकिंग के मामले में कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रही। कोरिया ने छह स्वर्ण और चार रजत पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इंजुन ने पहले छह तीर से दो परफेक्ट 10 और तीन 9 अंक वाले निशाना साधा जिससे सालुंखे 1-3 से पिछड़ गए। इस पर्व राष्ट्रीय चैंपियन ने दबाव से वापसी करते हुए तीसरा सेट दो अंकों से जीत कर स्कोर 3-3 कर दिया।

संखुले ने इसके बाद अपनी लय बरकरार रखी जबकि इंजुन पर दबाव में बिखर गये। सालुंखे ने 10 अंक के दो और एक 9 अंक का एक निशान साध कर 5-3 की बढ़त हासिल कर ली और फिर दो एक्स (निशाने के बिलकुल बीच में) के साथ शानदार अंत किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 64 अंक चढ़ा निफ्टी 19,400 के नीचे

मुंबई। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखी गई। आज के कारोबार में भले ही व्यापक सूचकांक लाल निशान में रहे, मगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के के शानदार प्रदर्शन की बदौलत फ्रंटलाइन सूचकांक बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा, धातु शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई, जबकि ऑटो और आईटी शेयरों में कमजोरी देखी गई। आज के कारोबार में सेंसेक्स 64 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 24 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 19,355.90 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 63.72 अंक यानी 0.10 फीसदी मजबूत होकर 65,344.17 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,633.49 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,246.40 तक आया।

रियल एस्टेट सेक्टर में पीई निवेश पांच फीसदी घटा

नईदिल्ली। रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून की तिमाही में सालाना आधार पर पांच फीसदी घटकर 1.9 अरब डॉलर रह गया है। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ऊंची ब्याज दरों की वजह से निजी इक्विटी फ्लो में कमी आई है। इससे पिछले साल की समान तिमाही में रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश दो अरब डॉलर रहा था। एनारॉक ने 'भारतीय रियल एस्टेट में पूंजी फ्लो पर-फ्लक्स 2023-24 की पहली तिमाही की निगरानी रिपोर्ट' में कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऊंची ब्याज दरों की वजह से पीई गतिविधियों में मामूली गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में पीई फ्लो 1.4 अरब डॉलर रहा था। वहीं 2020-21 की पहली तिमाही में यह 20 करोड़ डॉलर और 2019-20 की पहली तिमाही में 1.7 अरब डॉलर रहा था।

टोल कलेक्शन 18% बढ़कर 1,183 करोड़ रुपये हुआ

नईदिल्ली। आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का टोल राजस्व चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 18 फीसदी बढ़कर 1,183 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी ने सोमवार को बयान में यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में टोल कलेक्शन 1,000 करोड़ रुपये रहा था। बयान में कहा गया, 'आईआरबी और उसके निजी इनविट आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का जून महीने का टोल राजस्व 16 फीसदी बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दोनों इकाइयों के टोल कलेक्शन में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।' जून, 2023 में कंपनी ने 383 करोड़ रुपये का टोल राजस्व दर्ज किया, जो जून, 2022 में 329 करोड़ रुपये था। आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ मुरारका ने कहा, 'चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही काफी सकारात्मक दिख रही है।

ग्लोबल पीईटी आईपीओ लिस्टिंग, 6% प्रीमियम पर एंट्री

नईदिल्ली। कंपनी ग्लोबल पीईटी के शेयरों ने आज यानी सोमवार को बाजार में दमदार एंट्री की है। कंपनी के शेयर एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म एनएसई एसएमई पर 52 रुपये के भाव पर खुले यानी कि शेयरों को 6 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला। आईपीओ निवेशकों को 49 रुपये के भाव पर जारी हुए हैं। लिस्टिंग के बाद भी शेयरों की तेजी बढ़ती रही और ये 54.60 रुपये के अपर सर्किट पर पहुंच गया। ग्लोबल पीईटी के 13.23 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 27 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। यह इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 28 जून से 3 जुलाई तक खुला था। इसके शेयर 49 रुपये के भाव पर जारी हुए हैं। अब इस इश्यू के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। यह कंपनी पीईटी स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन बनाती है।

उम्मीदों और आशंकाओं के बीच चंद्रयान-3 की उड़ान

संदीप अग्रवाल

भारत का महत्वाकांशी मिशन चंद्रयान 3 उड़ान भरने के लिए तैयार है। चंद्रमा के बारे में जानकारी बढ़ाने के हमारे इस तीसरे प्रयास को इसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, इसरो का नया प्रक्षेपण यान एल वी एम-3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) सिस्टम। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर के 2.35 बजे और स्थान, सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र श्रीहरिकोटा। रॉकेट लांच होने से पहले ही सभी का दिल धक-धक कर रहा है। यह धकधक अगले दो हफ्ते तक जारी रहेगी, जब तक इसरो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा लेता। ज्ञातव्य है कि अभी तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के 38 प्रयास हो चुके हैं, जिनमें 52ब ही सफल रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में किसी विमान, रॉकेट या स्पेसशिप को इस तरह किसी सतह पर उतारा जाता है, जिससे वाहन या उसके पे लोड को ज्यादा क्षति न पहुँचे।

ऐसे दौर में जब भारत विश्व भर में एक स्पेस सुपर पॉवर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, हम लोगों को अपनी क्षमताओं पर संदेह क्यों हो रहा है? क्यों हमें द न्यूयॉर्क टाइम्स में हाल ही में छपी वह खबर आश्वस्त नहीं कर पा रही, जिसमें उसने भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सराहना की है। इसका जवाब है पिछले चंद्र मिशन को लेकर हमारा अनुभव। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। इस बार हम अति उत्साह का परिचय देने से बच रहे हैं। जीत मिलने से पहले ही पटाखा छोड़ना शुरू कर देने वाले लोगों के देश में यह खामोशी थोड़ी अजीब लग सकती है। लेकिन, कुछ मौके ऐसे होते हैं, जब शांति हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। यह एक ऐसा ही अवसर है।

ऐसे अवसर पहले भी कई बार दुनिया के

सामने आ चुके हैं। अपोलो-11, जो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान था, वह भी सवालों से घिरा हुआ था। अमेरिका पर आरोप है कि उसने रूस (तब सोवियत संघ) को नीचा दिखाने के लिए नवादा के रेगिस्तान में ऐसा दृश्य रचा था। अमेरिका के एक पूर्व नौसेना अधिकारी बिल केसिंग ने अपनी किताब बी नेवर वेंट टू द मून में इस मिशन के वास्तविक होने पर संदेह प्रकट किया था। अपने शक की पुष्टि करने के लिए केसिंग ने कई अकाट्य तर्क भी प्रस्तुत किए थे। 1980 में फ्लैट अर्थ सोसाइटी ने भी मिशन पर सवाल उठाए हैं। 21 जुलाई को इस मिशन को 54 साल होने जा रहे हैं, पर ये सवाल आज भी नासा और अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ रहे। जैसे कि, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो फोटो में अमेरिका का झंडा कैसे लहरा रहा है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि चार टन वर्जन वाले अंतरिक्ष यान के निशान चंद्रमा की सतह पर नहीं थे, जबकि आमस्ट्रांग के पैरों के निशान वहाँ नजर आ रहे हैं। आर्मस्ट्रांग की फोटो किसने खींची, क्योंकि उनके हेलमेट के काँच में दूसरा अंतरिक्ष यात्री काफी दूर खडा नजर आ रहा है, जबकि कायदे से फोटो खींचने वाले का अक्स वहां दिखाई देना चाहिए था। अपोलो-11 के करीब दस महीने पहले सितंबर 1968 में सोवियत संघ ने जॉन्ड - 5 स्पेसशिप चाँद पर भेजा था, जिसमें कुछ कछुए सवार थे। छह दिनों तक चंद्रमा के चक्कर लगाने के बाद यह क्रेश हो गया और हिंद महासागर में आ गिरा। दिलचस्प बात यह है कि इसके मलबे में, यान में सवार कछुए जीवित मिले। इससे पहले 12 सितंबर 1959 को लूना -2 लॉन्च किया गया था, जो दो दिन बाद चांद की सतह से टकरा गया। इसलिए चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने और सकुशल वापस लौटने वाला पहला यान होने का सेहरा अपोलो-11 के सिर बांधा गया। चंद्रमा पर अब तक 110 मिशन जा चुके हैं। इनमें 42 असफल रहे हैं। रूस और अमेरिका भी 40 से ज्यादा बार असफल रहने के बाद चंद्रमा को छू पाए थे। फिर सितंबर 2019 में, चंद्रयान-2 के असफल होने को हमने इतना ज्यादा दिल पर क्यों ले लिया? क्या यह सिर्फ एक मिशन का फेल होना नहीं था? शायद नहीं, क्योंकि चंद्रयान-2 के साथ हमारा एक बड़ा सपना भी जुड़ा था, जिसका टूटना, हमारे लिए इस मिशन की विफलता से ज्यादा आहत करने वाला था।

क्या अमेरिका कमजोर और चीन मजबूत हो रहा है

रहीस सिंह

अमेरिका के राजनीतिक अर्थशास्त्री लेस्टर थोरो ने अपनी किताब 'दि फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म' में लिखा है कि विश्व व्यापार व्यवस्था के नियम-कायदे हमेशा वर्चस्वशील अर्थव्यवस्थाओं ने तय किए और लागू कराए हैं। 19वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन ने यह भूमिका निभाई। 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने। लेकिन 21वीं सदी में आर्थिक प्रबंधन के नियम-कायदों की रूपरेखा बनाने, संगठित करने और उन्हें लागू कराने वाली कोई भी एक शक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका के प्रभाव में चल रही एक-ध्रुवीय व्यवस्था के दिन लद चुके हैं और एक बहुध्रुवीय संसार उभरकर विश्व रंगमंच पर आ चुका है। थोरो की यह बात कितनी सही है, इस पर सभी एकमत नहीं होंगे, लेकिन जो बदलाव दिख रहे हैं वे इस ओर इशारा जरूर करते हैं कि अमेरिका अब दुनिया का लीडर नहीं रह गया है। असल में, अमेरिका के अधिकांश मित्र अब चीन की ओर देख रहे हैं। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि चीन वैश्विक व्यवस्था में अपनी मजबूत जगह बनाने में काफी हद तक सफल रहा है, लेकिन उसका यह सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। इस परिवर्तन की शुरुआत सही अर्थों में वर्ष 2008 से ही हो गई थी, जब अमेरिका में लीमैन ब्रदर्स दिवालिया हुआ और अमेरिका एक ऐसे वित्तीय संकट से गुजरा, जिसका असर अभी तक बना हुआ है। यह असर अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। बाद के वर्षों में पूरा यूरोप आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। इसने यह पता चला कि विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों की तरफ से जो घोषणा की गई थी, वह पूरी तरह से सही नहीं थी। उनका कहना था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब डी-कपल हो चुकी है। यानी, किसी एक अर्थव्यवस्था को झटका लगने से अन्य देशों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इससे दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और अभी भी हो रही हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद यह तय हो गया कि अमेरिका अब ऐसा शक्ति केंद्र नहीं रहा, जिसके इर्द-गिर्द दुनिया घूमे। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था में भी ऐसे बुलबुले हैं, जिनके फूटने पर चीनी अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो सकती है, लेकिन इस समय अमेरिका की तुलना में चीन को निश्चित रूप से डिप्लोमैटिक सरप्लस हासिल है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को करीब से देखें तो इसमें कुछ विशेषताएं बिल्कुल साफ हैं। अब वैश्विक शक्ति के केंद्र में केवल अमेरिका नहीं है। हालांकि दुनिया दो ध्रुवों में अभी भी नहीं बंटी है। भारत, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि की किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं की जा सकती। ये जी-20, जी-7, क्वॉड, एससीओ, ब्रिक्स, आसियान, जैसे संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिशीलता के साथ-साथ दशा और दिशा भी सुनिश्चित करते हैं। अमेरिका, चीन और रूस के बीच बनते-बिगड़ते समीकरण दुनिया को अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक प्रभावित कर रहे हैं। सच यही है कि आज अमेरिका के मित्र देश ही नहीं, स्वयं अमेरिका भी चीन की तरफ देखता हुआ प्रतीत होता है। इसके प्रमाण के तौर पर एंटनी ब्लिंकन की अमेरिका यात्रा को ले सकते हैं। उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पेइचिंग यात्रा हुई, यूरोपियन कमिशन के चेयरमैन ने भी शी चिनफिंग के दरबार में हाजिरी लगाई। ईरान और सऊदी अरब निकट आए तो इसमें भी पेइचिंग की भूमिका निर्णायक रही। अब इस्राइल के प्रधानमंत्री भी पेइचिंग विजिट की तैयारी कर रहे हैं। मध्य-पूर्व में इस चीनी पैठ के बाद अमेरिका के लिए क्या कोई स्पेस बचा है? इस्लामी देशों की जहां तक बात है तो वे शीतयुद्ध के दौर से ही या तो अमेरिकी खेमे में चले गए या उनका अमेरिका की तरफ झुकाव रहा। अब ये चीन की ओर 60 डिग्री झुके दिख रहे हैं जबकि चीन 'हुई' और 'उइगर' समुदाय के खिलाफ मुहिम चला रहा है। पिछले दिनों ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामी कोऑपरेशन (ओआईसी) की बैठक में न केवल चीन को आमंत्रित किया गया बल्कि उसके प्रति समर्थन व्यक्त किया गया।

समान नागरिक संहिता की राह

अनिल तिवारी

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम साल चल रहा है और समय आ गया है कि पार्टी अपने कोर एजेंडा का तीसरा वायदा भी पूरा करे तथा वायदों को पूरा करने की उपलब्धि के साथ 2024 के आम चुनाव में जाए। भारतीय जनसंघ के गठन के वक्त संघ परिवार के पास जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का एजेंडा था। बाद के दिनों में समान नागरिक संहिता और फिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शामिल किया गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। अब मामला तीसरे वायदे का है। 2 वैसे तो सरकार ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा लिया है, लेकिन सवाल इसे पूरी तरह लागू करने का है। केंद्र सरकार ठोक बजाकर आगे बढ़ने की रणनीति पर चल रही है। प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल अथवा गुजरात जैसे राज्य में कानून लागू कर जन मन की टोह लेकर आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की थी।

2022 में उत्तराखंड में इस बहस ने जब तेजी पकड़ी थी जब भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। दोबारा सत्ता पाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश व भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा कर दी। मई 2023 तक समिति के पास ढाई लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे। समिति ने प्राप्त सुझावों का अध्ययन के बाद मसौदा तैयार कर लिया है। मसौदे में शादी की उम्र, विवाह पंजीयन, बहुपत्नी पर रोक, हलाला और इद्दत को खत्म करने, तलाक के नियम, भरण पोषण, गोद लेने का अधिकार, बच्चों की देखरेख, उत्तराधिकार कानून, जनसंख्या नियंत्रण, बच्चों की कस्टडी, लिव इन रिलेशनशिप पर गंभीरता से विचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है इसे जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया जाएगा।

लेकिन हाल में ही 4 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आये तो समान नागरिक संहिता के उनके प्रयास पर कुहासा छा गया। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ यूसीसी पर कोई चर्चा किए जाने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि जल्द से जल्द राज्य में यूसीसी लागू किए जाने के उनके दावे को लेकर पत्रकारों द्वारा कुरेदे जाने पर बस इतना ही कहा कि इसमें कोई देरी नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे लागू करने में अभी कोई जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। इस बीच समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेश के अधिकार पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ जानकार लोग प्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर किए जा रहे दावों को बेतुका और सार्वजनिक धन की फिजूलखर्ची बता रहे हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 स्पष्ट कहता है कि यदि समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो वह पूरे देश के लिए होगी। इसमें जो %राज्य% शब्द है उसका आशय प्रांत या प्रदेश नहीं वरन राष्ट्र-राज्य है। लिहाजा एक प्रदेश के स्तर पर समान नागरिक संहिता बनाने की कवायद ही अर्थहीन है। यह संविधान सम्मत भी नहीं है।

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में देशभर में यूसीसी कानून लागू करने का मुद्दा इसी आलोक में उठाया था। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जब एक घर में अलग सदस्यों के अलग कानून हो तो घर नहीं चल सकता, तो फिर अलग कानून से देश कैसे चलेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य (राष्ट्र) का कर्तव्य मानता है, लेकिन शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति पर अधिकार आदि सामाजिक मुद्दे समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर केंद्र को आगे आना चाहिए। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि पर्सनल लॉ में बदलाव को समान नागरिक संहिता लागू करने से जोड़ना अनुचित है। तमाम अधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन दलों का तर्क है कि किसी एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में ऐसे प्रावधान आज भी मौजूद हैं जो खासकर महिलाओं के प्रति भेदभावकारी हैं और भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में विधि आयोग ने भी परामर्श पत्र में लिखा है कि असमानता का मूल कारण भिन्नता नहीं बल्कि भेदभाव है। मोटे तौर पर समान नागरिक संहिता को लेकर देश में तीन प्रकार के विचार समूह सामने हैं। एक आशावादी, दूसरा शंकावादी और तीसरा कुशंकावादी। आशावादी समूह में वे लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि समान नागरिक संहिता आने से देश में सांप्रदायिकता नियंत्रित होगी। दूसरे वे हैं जो शंका करते हैं कि क्या देश में यह लागू हो सकेगी? क्या इसके कुछ ठोस परिणाम आ सकेंगे? और तीसरे में वे हैं जिनके मन में कुशंका है कि समान नागरिक संहिता उनके धार्मिक कानून को समाप्त करने के लिए लाई जा रही है।

लेकिन अधिकांश लोग समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं और वे मानते हैं कि प्रगतिशील समाज को अपनी धार्मिक व सामाजिक गैरजरूरी परंपराओं और धर्म के नाम पर चल रही रूढ़ियों को छोड़ना चाहिए तथा धर्म के नाम पर विषमतामूलक परंपराओं से ऊपर उठना चाहिए। प्रगतिशीलता का मतलब केवल मशीन और तकनीक के सुख का उपयोग नहीं है बल्कि एक उन्नत और खुले मस्तिष्क के साथ एक नए भविष्य की ओर देखने वाली दृष्टि और सोच ही प्रगतिशीलता है। इस बीच समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक के दौरान जनजाति समाज के लोगों को इसके दायरे से बाहर रखे जाने की पुरजोर मांग की गई। सिख समुदाय की ओर से भी कानून को लेकर नकारात्मक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अकाली दल और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी समान नागरिक संहिता के विरोध का संकेत कर रही हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने के लिए भाजपा को विपक्ष साधने के साथ साथ अपनों को भी सहमत करना होगा। हालांकि समान नागरिक संहिता कानून के रास्ते में अभी ढेर सारी रुकावटें हैं, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यह प्रयास भी करना चाहिए कि देश में समान नागरिक संहिता को लेकर आमराय बने और प्राचीन कट्टरताओं से मुक्ति पाकर एक सभ्य और बराबरी का समाज बनाने का प्रयास हो। इस कानून के लागू होने से सांप्रदायिकता कम होगी, देश की एकता मजबूत होगी, सदियों से स्थापित विषमता और शोषण से मुक्ति पाकर तरक्की के रास्ते खुलेंगे साथ ही 42 वें संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया सेकुलर शब्द सही अर्थों में लोक व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

इस प्रकार बारह अंगों का उल्लेख मिलता है, जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक तीनों भागों में वर्णित किये गये हैं। इनमें चन्द्रमा, ब्रह्मा, दिशाएँ, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, प्रजापति एवं यम ये सभी बारह इन्द्रियों के अधिदेवता रूप से बारह नाड़ियों में अवस्थित रहते हैं, ये ही प्राण के अंग कहे गये हैं। इन अङ्गों को जानने वाला ही ज्ञाता कहा गया है।

तदनन्तर वह काल प्रभाव के वशीभूत हो विवेक एवं आत्मज्ञान को प्राप्त करके उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर क्रमशः एक स्थान (कक्षा) से दूसरे स्थान (कक्षा) को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् वह अपने प्राण तत्त्व को मूर्द्धास्थान में स्थित करके योग के अभ्यास में निरत (तत्पर) हो जाता है। योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत होती है।

जो श्रेष्ठ साधक योगी निरन्तर अपनी ज्ञानयोग की साधना में मनोयोगपूर्वक संलग्न रहता है, वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। वह विकारों में स्थित शिव (परब्रह्म) का निरन्तर दर्शन करता रहता है; किन्तु शिव में विकार का नहीं।

ऐसा श्रेष्ठ योगी सर्व विकारों से रहित ब्रह्म का अनन्य भाव से चिन्तन करे। जिसे इस प्रकार का ज्ञानयोग प्राप्त नहीं होता, उसे सिद्धि नहीं मिलती। इस प्रकार योग के निरन्तर अभ्यास से प्राणों के द्वारा मन का निरोध करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह छुरी की पैनी धार के सदृश दृढ़ निश्चयी होकर (मोहबन्धन) काट दे। यम-नियमादि अष्टाङ्गयोग की साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा प्रादुर्भूत होती है। योग के दो मार्ग बतलाये गये हैं, जिनमें प्रथम ज्ञानयोग एवं द्वितीय कर्मयोग है।

हे श्रेष्ठ ब्रह्मन्! अब क्रिया-योग (कर्मयोग) के सन्दर्भ में वर्णन करते हैं। जिस योगी का चित्त व्याकुलता (व्यग्रता) से विहीन है, वह विषय-भोगों के बन्धन में कभी नहीं पड़ता। हे द्विजश्रेष्ठ! संयोग भी दो प्रकार के होते हैं। कर्म और कर्त्तव्य द्वारा शास्त्रानुकूल कर्मों में निरन्तर मन को नियुक्त किये रहना ही कर्मयोग कहलाता है। चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किये रहना ज्ञानयोग कहलाता है। इससे सभी तरह की आत्मकल्याण सम्बन्धी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य दोनों प्रकार के योगों का विकाररहित भाव से सेवन करता है, वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। शरीर एवं इन्द्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भावना ही यम कहलाती है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं । अनुरक्ति परे तत्त्वे सततं नियमः स्मृतः । परमात्म तत्त्व से निरन्तर अनुराग (प्रेम आसक्ति) रखना ही नियम कहलाता है। समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है।

क्रमशः ...

विश्व जनसंख्या दिवस : विकराल होती जा रही जनसंख्या

राजेश कश्यप

जनसंख्या को नियंत्रित रखने और लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया जाता है। इसकी शुरूआत 11 जुलाई, 1989 को हुई थी। उस समय विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ती हुई 5 अरब के आंकड़े पर पहुंच चुकी थी। विकराल होती जनसंख्या के बाद पैदा होने वाली विकट चुनौतियों ने सभी देशों में चिंता का सबब बनने लगा। तब इस विशेष दिवस को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा जनसंख्या दिवस घोषित करके प्रतिवर्ष हर जनमानस में बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता पैदा करने और परिवार नियोजन का संकल्प लेने का अभियान शुरू करना पड़ा।

आज विश्व की कुल आबादी 7 अरब को भी पार कर चुकी है। यदि विश्व की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो वर्ष 2100 में यह आंकड़ा 11 अरब के आंकड़े को छू लेगा। आज पूरा विश्व विकराल होती जनसंख्या और बढ़ती विकट चुनौतियों का आकलन करके बेहद चिंतित है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आर्थिक सन्तुलन तो गड़बड़ाया ही है, साथ ही प्राकृतिक सन्तुलन को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और संसाधन निरन्तर कम होते चले जा रहे हैं।

हमारे देश की जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और निरन्तर अनेक विकट चुनौतियां चिन्ता का सबब बन रही हैं। देश की जनसंख्या गत 2001-2011 के दशक में 17.7 प्रतिशत की दर से बढ़ती हुई 1,21,05,69,573 हो गई है, जिसमें 83,34,63,448 पुरूष और 37,71,06,125 महिलाएं शामिल हैं। जनसंख्या के मामले में हमारा देश विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। एक अनुमान के मुताबिक सन् 2030 तक चीन को पछाड़कर, भारत विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.23 प्रतिशत निवास करती है, जबकि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 2.45 प्रतिशत ही है। एक नजरिए से विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। कहना न होगा कि विकराल होती जनसंख्या के कारण देश की उन्नति एवं प्रगति पर बड़े घातक प्रभाव पड़ रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। विकराल होती जनसंख्या के कारण रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। देश में गरीबी और भूखमरी का साम्राज्य निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। विकासशील देशों में गिने जाने वाले भारत देश में आज भी 2.2 करोड़ से अधिक लोग खुले आसमान के नीचे खाना खाने को मजबूर हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार दुनिया की 64 प्रतिशत अति गरीब आबादी महज पाँच देशों में रहती है, जिनमें भारत (33 प्रतिशत), चीन (13 प्रतिशत), नाईजीरिया (7 प्रतिशत), बांग्लादेश (6 प्रतिशत) और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (5 प्रतिशत) शामिल है।

बेहद विडम्बना का विषय है कि इनमें भारत का प्रथम स्थान है। अति दरिद्रता के चलते देश में गैर-कानूनी होने के बावजूद छह लाख से अधिक लोग मैला ढ़ोने को विवश हैं। देश के 56 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। नैशनल सैम्पल सर्वे कमीशन के अनुसार देश में करीब 52 प्रतिशत किसान कर्जदार हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रतिदिन औसतन 46 किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारत का है। देश में मातृ-मृत्यु दर के आंकड़े भी बड़े चैंकाने वाले हैं।

सबक देते फ्रांस के दंगे

फ्रांस्वा इ्युबे

फ्रांस में हाल में जो दंगे भड़के, वे हैरान करने वाले नहीं हैं। ये दंगे भी ठीक उसी तरह से सामने आए, जैसे 1981 में ल्यों के पूर्वी उपनगरों में भड़के थे। तब हुए उन दंगों को आज %समर ऑफ मिंगुएत% भी कहा जाता है, जिसमें पुलिस एक नौजवान को मार देती है या घायल कर देती है और फिर उस इलाके और आसपास के उपनगरों में हिंसा भड़क उठती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति, आपका पड़ोसी तक बेकाबू हो जाता है, जैसा कि 2005 के दंगों में हुआ था और आज भी हो रहा है।

फ्रांस में पिछले चालीस साल में हुए शहरी विद्रोहों में ऐसे युवाओं का गुस्सा हावी रहा है, जो शासन और देश के प्रतीकों-जैसे, टाउन हॉल, सामाजिक केंद्रों, स्कूलों और दुकानों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। यह ऐसा गुस्सा है, जो सबके सामने लोगों को अपने ही पड़ोस को नष्ट कर देने के लिए उकसाता है। सभी नागरिक ऐसी हरकतों की निंदा करते हैं, लेकिन यह भी समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधि, संघ, चर्च और मस्जिदें, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक अपनी लाचारी स्वीकार कर लेते हैं और इससे एक संस्थागत और राजनीतिक खालीपन सामने आता है।

ऐसे सभी विद्रोहों में, 1981 की %समर ऑफ मिंगुएत% में भड़का विद्रोह ही एकमात्र था, जिसने सामाजिक आंदोलन का रास्ता दिखाया था। दिसंबर, 1983 में समानता और नस्लवाद के खिलाफ जो मार्च निकला था, वह इसी का परिणाम था। इसमें एक लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और मीडिया

ने इसे प्रमुखता से जगह दी थी। फ्रांस में यह अपनी तरह का पहला प्रदर्शन था। इसके बाद अभी तक ऐसा कोई आंदोलन उभरता नहीं दिखा है।

हर दंगे में राजनेता वही पुरानी घिसी-पिटी भूमिकाएं निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। दक्षिणपंथी हिंसा की निंदा करते हैं, आस-पड़ोस और पुलिस का शिकार हुए लोगों को कलंक ठहराने लगते हैं, वामपंथी अन्याय की निंदा करते हैं और सामाजिक नीतियों का वादा करते हैं। साल 2005 में तब के आतंरिक मामलों के मंत्री निकोलस सरकोजी पुलिस के पक्ष में खड़े थे। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नेंतेरे में पुलिस की गोली से मारे गए लड़के के लिए सहानुभूति जताई है, पर संबंधित पड़ोसी इलाकों में राजनेताओं और राष्ट्रपति की बात शायद ही लोग सुनते हैं। हम तब तक चुप्पी साधे रहते हैं, जब तक कि बॉनलिए (फ्रांस के उपनगर) और यहां की पुलिस की समस्याओं को व्यापक रूप से समाज फिर से नहीं खोजने लगता। फ्रांस के शहरी इलाकों में बार-बार भड़कने वाले दंगों और उनके परिदृश्यों से कुछ आसान सबक मिलते हैं। पहला तो यही कि देश की शहरी नीतियां अपने लक्ष्यों से चूक जाती हैं। पिछले चालीस वर्षों में आवास और सुविधाओं के लिए काफी कोशिशें हुईं। अपार्टमेंट बेहतर गुणवत्ता वाले हैं, सामाजिक केंद्र, स्कूल और कॉलेज हैं, सार्वजनिक परिवहन है। दूसरी ओर, लाभ से वंचित उपनगरों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में गिरावट आई है। ज्यादातर लोग गरीब या आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं और या तो वे अप्रवासियों के वशंज हैं या स्वयं अप्रवासी हैं।

सबसे पहले, जो लोग जल्दी बॉनलिए छोड़ कर जा सकते हैं, उन्हें अवसर और संसाधन दिए जाते हैं और ऐसा सिर्फ तभी किया जाता है, जब दूर के गरीब लोगों को वहां बसाया जाता है। इस तरह बनाए माहौल से जहां स्थितियां सुधर रही हैं, वहां सामाजिक हालात भी बेहतर हो रहे हैं। हालांकि हो सकता है, सुविधाओं से वंचित इलाकों के बारे में लोग बात करने को इच्छुक न हों, पर यहां काम करने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया को वास्तव में एक यहूदी बस्ती में देखा जा सकता है, जहां पड़ोसी इलाकों और उनके माहौल के बीच बढ़ती खाई साफ है, पर यह बस्ती भीतर से मजबूत और आत्म-नियंत्रित है। नकदी और स्थानीय प्रतिनिधियों की सदिच्छा के बावजूद लोग समाज से बहिष्कृत सिर्फ इसलिए महसूस करते हैं, क्योंकि उनके मूल, संस्कृति या धर्म अलग हैं। सामाजिक नीतियों और प्रतिनिधियों के काम के बाद भी बस्तियों के पास अपने संस्थागत या राजनीतिक संसाधन नहीं हैं। जबकि अक्सर कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले उपनगरों को वाम झुकाव वाले राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और लोकप्रिय शिक्षा आंदोलनों के मजबूत समर्थन से काफी लाभ मिला है, मगर आज के उपनगरों के पास शायद ही अपना कोई नेता है, जो आवाज उठाए।

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षकों की सदिच्छा में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां नहीं रहते, जहां ये लोग काम करते हैं। यह दूरी दोनों तरीके से काम करती है और पिछले दिनों हुए दंगों से पता चला है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और एसोसिएशनों की ऐसी बस्तियों पर कोई पकड़ नहीं रह गई है, जहां लोग अपने को बेसहारा महसूस करते हैं। शांति की अपीलों की अनसुनी की जा रही है। यह दरार सिर्फ सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक भी है। हम तेजी से नौजवानों को पुलिस के साथ जूझते हुए देख रहे हैं। दोनों समूह अपनी-अपनी नफरतों और इलाकों के साथ %गिरोह% की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में राज्य कानूनी हिंसा और नौजवान अपने वास्तविक या संभावित अपराध के दायरे में सिमट कर रह गए हैं। पुलिस को इस आधार पर मशीनी रूप से नस्लवादी माना जा रहा है कि कोई भी नौजवान पहली नजर में संदिग्ध होता है। नौजवान पुलिस से नफरत करते हैं, इससे पुलिस नस्लवाद और युवा हिंसा को बढ़ावा मिलता है। ऐसा युद्ध आमतौर पर बहुत ही निचले स्तर पर खेला जाता है। जब कोई नौजवान मारा जाता है, तो हर जगह हर चीज में विस्फोट हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसी दुखद पुनरावृत्ति में कुछ नया है। पहला तो दक्षिणपंथ का उदय है, जो राजनीतिक परिदृश्य के सिर्फ एक तरफ ही नहीं है। विद्रोह के नस्लवादी कारण तेजी से उभर रहे हैं, जो बर्बरता और आप्रवासन की बात कर रहे हैं और इस बात का डर है कि इससे चुनावी कामयाबी मिल सकती है। दूसरा यह कि राजनीतिक वामपंथ को राजनीतिक और बौद्धिक तौर पर लकवा मार गया है। ऐसा नहीं लगता कि इसने पुलिस सुधार के अलावा किसी तरह का कोई राजनीतिक हल सुझाया हो।

बापू की दिनचर्या

सायंकालीन वायु सेवन

सायंकाल के भोजन के बाद बापू घूमने निकल जाते। किसी कारणवश कभी वे शाम को न टहल पाते तो सोने के पहले अवश्य टहलते। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण, एक बार सन् 1920 में, जब उनका शाम का टहलना न हो सका और आधी रात बीत गई तब वे आधी रात के बाद टहले। यरवदा में सन् 30 में बापू शाम को भोजन के बाद नियमित रूप से टहलते। सेवाग्राम में सायंकालीन आहार से निवृत्त होकर वे उसी मार्ग पर प्रातः काल की तरह टहलने जाते। जाड़े के दिनों में वे शाम को लगभग छह बजे टहलने निकलते। शाम को बापू लगभग आधा घंटा तक टहलते, किंतु सन् 1930 में उन्होंने एक बार अपने सायंकालीन वायुसेवन का समय लगभग दूना कर दिया था, जबकि उन दिनों वे सुबह भी देर तक घूमते। इस पर काका साहब ने उनसे कहा कि स्वास्थ्य पर इसका कहीं विपरीत प्रभाव न हो। उस समय बापू ने बताया कि उनको भीतर से कुछ विशेष शक्ति प्रतीत होने लगी थी इसीलिए उन्होंने जान-बूझकर वायु सेवन के समय में वृद्धि की। बापू वायु सेवन को ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का अंश मानते और कहते मनुष्य को नित्य प्रातःकाल दिनभर कार्य करने के लिए जो शक्ति प्राप्त कि होती है, उसे उसको शयन के समय तक खर्च कर डालना चाहिए। यही सच्चा अपरिग्रह है। यदि श्रद्धापूर्वक ऐसा नहीं किया जाता है तो श विकार का रूप ले लेती है। जब हमें नित्य अपेक्षित शक्ति प्राप्त हो ही जाती है, तब उसे खर्च करने में कंजूसी क्यों की जाए? उसे क्यों बचाया जाए? उनकी मान्यता थी कि शरीर में जो वीर्य उत्पन्न होता है, परिश्रम द्वारा पसीने के रूप में उसे निकाल देना या रूपांतरित कर देना रात्रि में अच्छी नींद आने और विकार से बचने की दृष्टि से अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में- अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य—दोनों दृष्टियों से पूर्ण परिश्रम-खासकर सायंकालीन वायु सेवन उपयोगी है। प्रातः काल की भाँति सायंकाल के वायु-सेवन के समय भी जनसमूह बापू के साथ हो लेता। कभी-कभी तो वे अपने परिवार के अतिरिक्त, आश्रम से संबंधित लोगों के बालकों के साथ निकल पड़ते और उनको दौड़ाकर स्वयं भी उनके साथ दौड़ लगाने लगते।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

मोहम्मद अकबर बनेंगे कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष

रायपुर। पिछली बार कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के प्रमुख रहे वर्तमान उप मुख्यमंत्री सिंहदेव द्वारा यह पद न लेने का ऐलान के बाद कांग्रेस की ओर से दो नाम प्रमुखता से आगे आए मंत्री रविन्द्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर का,लेकिन विभागीय काम व विधानसभा के कार्यदायित्व की अधिकता को देखते हुए श्री चौबे की जगह अकबर को यह जिम्मा सौंपने का फैसला पार्टी संगठन की ओर से लगभग लिया जा चुका है केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। अकबर काफी सुलझे हुए अनुभवी व्यक्ति हैं और जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों व आवश्यकताओं को वे जानते समझते हैं।

अजय चंद्राकर भाजपा आरोप पत्र समिति के संयोजक, पांडेय और चौधरी सदस्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र समिति गठित की है। धमतरी जिले के कुरुद से बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। वहीं सीनियर नेता प्रेम प्रकाश पांडेय और महामंत्री ओपी चौधरी को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश स्तरीय समिति की घोषणा की है। इसे लेकर प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी ने शनिवार को ही अपने घोषणा पत्र समिति के सदस्यों की भी घोषणा की थी। इसका संयोजक सांसद विजय बघेल बनाए गए हैं। इसके पूर्व प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी बनाया था। वहीं दूसरी ओर धरमलाल कौशिक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय कार्यसमिति में भी सदस्य बनाया गया है।

जोगी कांग्रेस का प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल गिरफ्तार

राजनांदगांव। पुलिस की आनलाइन सट्टा महादेव एप पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में रायपुर पुलिस ने महादेव एप बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर पुलिस ने जोगी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। नवीन अग्रवाल को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। देर रात एक बजे गिरफ्तारी हुई है इसलिए स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं लग पायी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रात को ही रायपुर लेकर पहुंच गई थी। इससे पहले कोरिया पुलिस ने आनलाइन सट्टे को लेकर रायपुर के विनय अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। विनय अग्रवाल के खिलाफ कोरिया में राज्य शासन के जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद कोरिया पुलिस की स्पेशल टीम रायपुर पहुंचकर विनय अग्रवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस की स्पेशल टीम आरोपी से खम्हारडीह थाना में प्रारंभिक पूछताछ के बाद देर रात कोरिया के लिए रवाना हुई। दोनो ही गिरफ्तारियों से माना जा रहा है कि बड़ा खुलासा हो सकता है।

चंदन व जांगिड़ आज आएंगे

रायपुर। एआईसीसी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. चंदन यादव व संयुक्त सचिव एवं सह-प्रभारी विजय जांगिड़ आज रायपुर आ रहे है। उक्त जनकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि डॉ. चंदन यादव मंगलवार को दोपहर 1.45 बजे नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे एवं न्यू सर्किट हाउस जायेंगे। दोपहर 2.15 बजे सर्किट हाउस में कांग्रेसजनों से भेंट एवं चर्चा करेंगे।वहीं दूसरी ओर संयुक्त सचिव एवं सह-प्रभारी विजय जांगिड़ सुबह 9 बजे नई दिल्ली से विमानतल रायपुर पहुंचेंगे एवं फारेस्ट रेस्ट हाउस-वनश्री के लिये रवाना होंगे। सुबह 9.30 बजे वन-श्री पहुंचकर कांग्रेसजनों से भेंट एवं चर्चा करेंगे।

सिंहदेव के इंकार के बाद किसी और के सर पर ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस के घोषणा पत्र की कमान मोहम्मद अकबर को दिए जाने की चर्चाओं को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र में झूठ परोसा था, इस बार टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से इंकार कर दिया है। कांग्रेस इस बार किसी और के सर पर ठीकरा फोडना चाह रहे हैं इसीलिए नए-नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। पुराने चेहरे पीछे हट रहे हैं, उनके घोषणा पत्र की कोई योजनाएं संचालित नहीं हो पाई। भाजपा के आरोप पत्र समिति गठन को लेकर कश्यप ने कहा कि वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर को संयोजक बनाया गया है, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ओपी चौधरी समेत तीन लोगों की समिति बनी है ये तय करेंगे किन मुद्दों को लेकर पत्र तैयार करेंगे।

हटकेश्वर महादेव में विकास उपाध्याय ने जलाभिषेक किया

रायपुर। सावन सोमवार के पहले दिन विधायक विकास उपाध्याय महादेवघाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने बेलपत्र व जलाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इसके अलावा सरोना स्थित शिव मंदिर एवं पश्चिम विधानसभा के अन्य मंदिरों में भी जाकर पूजा अर्चना कर लोगों के सुख एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने एवं मनोकामना मांगने का यही एक अवसर होता है। सावन के महीने में भगवान शिव अति प्रसन्न होकर सबकी मुरादें पूरी करते हैं।

जिसको बीजेपी की आइडियोलॉजी पता नहीं, वह घोषणा पत्र बनाएंगे

■ **विस में भाजपा चिल्ल चिल्लाकर बोल लें रमन सिंह जब तक नहीं हटेंगे तब तक बृजमोहन, चंद्राकर और प्रेमप्रकाश का कुछ नहीं हो सकता - भूपेश**

रायपुर। बालोद जिला रवाना होने से पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिसको बीजेपी की आइडियोलॉजी पता नहीं है वह घोषणा पत्र बनाएंगे। विधानसभा में भाजपा चिल्ल चिल्लाकर बोल लें रमन सिंह जब तक नहीं हटेंगे तब तक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और प्रेमप्रकाश पांडेय का कुछ नहीं हो सकता।

बघेल ने कहा कि भाजपा ने 2013 में संकल्प लिया था। किसानों का दाना दाना धान खरीदेंगे, डबल इंजन की सरकार ने फैसला लिया 10 क्विंटल धान खरीदेंगे क्यों उस समय दाना दाना धान नहीं खरीदा गया ? बोनस क्यों नहीं दिया गया, किसके कहने पर रोका गया। रमन सिंह किसानों को ठगने का काम किया। हमने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की तो श्रेय लेने में लगे हुए है। 2018 में जनता ने 15 सीटों पर बीजेपी को समेट दिया झूठ के सहारे जनता के बीच नहीं जा सकते। ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे रमन सिंह ने ठगा नहीं। हर वर्ग को ठगने का काम रमन सिंह ने किया। शराब को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यदि शराब फैक्ट्री से शराब की पेटी निकली तो सबसे पहले डिस्ट्रेलरों पर कार्रवाई होना चाहिए था। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई रमन सिंह की सरकार में शराब को लेकर पॉलिसी बनाई। कॉर्पोरेशन के माध्यम से शराब बिक्री का प्रावधान किया गया। इन लोगों से रमन सिंह के क्या संबन्ध है, सिर्फ 3 डिसलर से रमन सिंह से क्या संबन्ध है। रमन सिंह बताए दूसरे डिसलरो को क्यों मौका नहीं दिया गया। डिस्टलर्स को नोटिस जारी किया गया है। राजस्व में कमी आई है तो कार्रवाई भी होगी और वसूली भी की जाएगी। 2020 का मामला है, चुनाव देखकर ही ईडी आईटी के माध्यम से लडना चाहते हैं। कोई भी वर्ग इनके साथ नहीं है, केवल इंडी और आईटी के माध्यम से लडना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोप समिति और अन्य समितियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कितना भी विधानसभा में चिल्ल चिल्लाकर बोल लें। रमन सिंह को जबतक नहीं हटेंगे तब तक बृजमोहन, अजय चंद्राकर और प्रेमप्रकाश पांडे का कुछ नहीं हो सकता जो लोग जीवनभर बीजेपी का साथ दिए, उनको घर बैठा दिया गया।

विजय बघेल को घोषणा पत्र की जिम्मेदारी दी गई है। जिसको बीजेपी की आइडियोलॉजी पता नहीं, वह घोषणा पत्र बनाएंगे, विजय बघेल तो खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए है, बीजेपी में नेतृत्व का अकाल हो गया है। बीजेपी के धान खरीदी वाले आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं इनकी सब बातें मानने को तैयार हूं। केवल बताए की 2014 में बीजेपी ने 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का फैसला क्यों किया ? केंद्र सरकार कर रही है तो रोका किसने, किसानों की धान खरीदी करने से, रमन सिंह और बीजेपी बताए पिछले साल 107 लाख मैट्रिक टन खरीदे थे, इस साल 125 से 140 लाख मैट्रिक टन तक जाएगा बारिश अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छा होगा लाखों किसानों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया और आर्थिक क्षति क्यों पहुंचाई।

भाजपा का घोषणा पत्र धरातल पर उतरने वाला होगा : विजय बघेल

रायपुर। दुर्ग सांसद विजय बघेल को भाजपा ने घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है,कहा है कि जल्द ही समिति की बैठक लेकर सभी परिस्थितियों पर पहले चर्चा करेंगे। इतना जान लें कि हमारा घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा नहीं होगा। सच्चे संकल्प पत्र के रूप में हम घोषणा पत्र बनाएंगे।पहली प्राथमिकता लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप घोषणा पत्र बने। सबसे बड़ी चुनौती है कि घोषणा पत्र धरातल पर उतरने वाला हो। बघेल ने इस बात को खुलकर स्वीकारा कि 2018 में हमारी सरकार जो चली गई, उसका मुख्य कारण कांग्रेस के घोषणा पत्र रूपी झूठ का पुलिंदा ही था। आज साढ़े चार साल बाद भी कई घोषणाएं धरातल पर नहीं आई है। कांग्रेस के 36 वादों में एक भी वादा धरातल पर सही ढंग से नहीं नजर आया। धान, किसान जैसे मुद्दों को लेकर बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की चावल खरीदी की सही जानकारी जनता तक पहुंचाना है। कांग्रेस की जितनी गारंटी हैं, उसका जमीन पर अभी क्या स्थिति है। पुरानी पेंशन योजना में इस सरकार को क्या भार पड़ रहा है। जब ये सरकार में रहेंगे नहीं तब यह लागू होगा। पुराना पेंशन कांग्रेस का मकड़ जाल है। बघेल ने कहा कि शराबबंदी पर जनता के सुझाव के अनुसार काम करना है। कांग्रेस ने शराबबंदी करने का वादा किया था, इसमें क्या हुआ सभी को जानकारी है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी, जय वीरू ने साथ छोड़ा : केदार गुप्ता

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को लेकर तंज कसा है। भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान की ओर से टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बावजूद कांग्रेस में गुटबाजी, अंतर्कलह, खींचतान चल रही है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में भी दो गुट बन गए हैं। एक गुट भूपेश बघेल को चाहता है, तो दूसरा गुट टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाता है। दिल्ली में भी जमकर गुटबाजी हो रही है। भयंकर विस्फोट छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। ये बातें मीडिया में भी स्पष्ट हो चुकी हैं। सीएम भूपेश और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले घोषणा पत्र के जय-वीरू की जोड़ी में से जय ने साथ छोड़ा कि वीरू ने साथ छोड़ा। अब यह एक अकेला रह गया है।

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सिंहदेव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह घोषणापत्र समिति में नहीं रहेंगे। यह बहुत बड़े असंतोष को स्पष्ट करता है। बहुत बड़े कांग्रेस की वादाखिलाफी को स्पष्ट करता है। बाबा ने बहुत पहले ही ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। ग्रामीणों के आवास भूपेश सरकार नहीं बना पा रही थी। प्रधानमंत्री ने पूरा पैसा दिल्ली से अपने हिस्से का भेज दिया था। सीएम भूपेश पीएम आवास पर रोक लगाए बैठे हैं। इससे नाराज होकर बाबा ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया था। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस संगठन को बड़ा लंबा पत्र लिखा था।

पत्र में कहा था कि हमने गंगाजल लेकर कसम खाई, जो वादे किए उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। बाबा इस बार के चुनाव घोषणा पत्र समिति में रहना भी उचित नहीं समझा। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर बाबा तो राजा है और वह जो बोले वह ना हो कितनी बार कांग्रेस सरकार पर विश्वास करेंगे। सरकार के उपमुख्यमंत्री ही अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।

कांग्रेस का पंजा नौनिहालों के भविष्य पर कस रहा शिकंजा: साव

रायपुर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने शिक्षक विहीन शालेय बच्चों द्वारा सीएम हाउस में अपनी किताब कॉपी छोड़ देने को सरकार के तबादला उद्योग की देन बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में हर मामले में सिंडिकेट काम कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षा क्षेत्र को भी नहीं बख्शा। छत्तीसगढ़ का भविष्य खतरे में है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है कि शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बताने वाले मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र पाटन के 19 स्कूल भी एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हों तो आसानी से समझा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। इससे दुर्भाग्य जनक स्थिति क्या हो सकती है कि आज महासमुंद के बच्चों ने मुख्यमंत्री निवास के सामने कॉपी किताब छोड़ दिये, कल दूसरे स्थानों के बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की दुर्दशा एक जैसी है। भूपेश बघेल के राज में छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा का स्तर रसातल में पहुंच गया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में राज्य देश भर में तीसवें पायदान पर है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर तबादला उद्योग चला रहे हैं। कांग्रेस का पंजा छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के भविष्य पर शिकंजा कस रहा है। साव ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार के संरक्षण में शिक्षा विभाग में तबादला उद्योग चरम पर था और पूरे प्रदेश में तरह -तरह की धांधली व रिश्वतखोरी, तबादले का भय दिखाकर अवैध वसूली, मनचाही जगह पोस्टिंग की सौदेबाजी, एक ही जिले में दो अलग -अलग तबादला आदेश, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पुराने जिलों से नए जिलों के तबादले के गोरखधंधे की शिकायत आम थीं, तब भाजपा ने चेताया था कि अवैध कमाई के लिए शिक्षा का कबाड़ा न करें लेकिन जिस सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री तक पर तबादले के धंधे में शामिल होने के आरोप लगते हों, उस सरकार ने आंख नहीं खोली क्योंकि सारा खेल तो संगठित गिरोह ही संचालित कर रहा है।

रमन बताएं 10 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय किसका था : भूपेश

रायपुर। बीजेपी ने साल 2013 में ये संकल्प लिया था कि हम किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार ने फैसला लिया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि केंद्र केंद्र सरकार खरीदती है, तो रमन सिंह यह बताएं कि 10 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय किसका था। क्यों उस समय एक-एक दाना धान नहीं खरीदा गया? किसके कहने से रोका गया? बोनस किसके कहने से रोका। आपने तो हर साल बोनस देने की बात कही थी। चुनाव के पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। इसलिए किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीटों पर समेट दिया। अब तो 13 रह गए हैं। बीजेपी अब झूठ मत बोले। बीजेपी बहुत झूठ बोल चुकी। अब झूठ के सहारे आप जनता किसानों के बीच में नहीं जा सकते। हर वर्ग को ठगने का काम रमन सिंह ने किया है। ये बातें सीएम भूपेश बघेल ने बालोद जिला रवाना होने से पहले पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपेड में कहीं। उन्होंने कहा कि 2 साल बोनस और 3 साल खोनस। इस नीति पर रमन सिंह चलें रमन सिंह लगातार किसानों को ठग रहे हैं। किसानों को बार-बार नहीं ठग सकते। छत्तीसगढ़ के किसानों ने उन्हें बहुत मौका दिया। जैसे ही हमने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की। वह श्रेय लेने के लिए कूद पड़े। आरोप लगाया कि रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं। जिसको रमन ने ठगा नहीं। सब को ठगने का काम किया है। किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, गरीबों, युवाओं, व्यापारियों सबको ठगने का काम किया। रमन सिंह के शराब के आरोप पर कहा कि फरवरी 2020 में आईटी की रेड पड़ी थी। अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रही है कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक्साइज ड्यूटी बिना पटाए शराब पेटियां फैक्ट्री से निकली है। यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए निकली है, तो सबसे पहले डिस्टलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी। जो वहां पदस्थ थे उनकी थी, उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं। न उनकी अचल संपत्ति अटैच की, ना उनके बैंक खाते को सीज किया गया और और जब आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कितना हमने संपत्ति पकड़ा।

मेरे खिलाफ यूसीसी को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी : नंदकुमार साय

रायपुर। धमतरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी को नुकसान नहीं होने की बात कहने वाले नंदकुमार साय अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ यूसीसी के समर्थन को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। साय ने कहा कि मैंने कभी भी यूसीसी का ना तो समर्थन किया है ना ही कोई विरोध किया है। यूसीसी को लेकर मेरे नाम से यह फैलाया जा रहा है कि, मैंने इसका समर्थन किया है, जबकि मैंने ना तो इसका समर्थन किया है और ना ही विरोध किया है। यह बात पूरी तरह से गलत है।मैं इसका खंडन करता हूं।

कांग्रेस नेता नंदकुमार साय ने कहा कि यूसीसी पर मैंने कोई अभिमत नहीं दिया है। मैंने यह कहा था कि इस पर सभी के विचार आमंत्रित किया जाए। इस विषय को जब तक देखा नहीं जाएगा, जब तक हम समझ नहीं लेते अपना अभिमत कैसे दे सकते हैं। इसे लेकर मेरे नाम से कई बातें प्रसारित की जा रही है कि मैंने इसका समर्थन किया है या फिर अभिमत दिया है। जो भी लोग यह बातें कह रहे हैं वह पूरी तरह से गलत कह रहे हैं। यूसीसी को लेकर साय ने धमतरी में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सभी लोगों को समझने की जरूरत है। एक सामान्य नीतियां सभी के लिए समान रूप से हो, सबके लिए एक समान हो तो इससे किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको समझना है। इसके आने से कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून। चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। यूसीसी लागू होने पर अगर अपराध एक जैसे होंगे, तो सजा भी एक जैसी मिलेगी। अभी तलाक, विवाह, गोद लेने के नियम और संपत्ति विरासत पर धर्म के हिसाब से कानून है। मुस्लिम समाज में शरिया के आधार पर यह तय किया जाता है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बना रखे हैं।हालांकि, हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो। क्रिमिनल मामलों में एक जैसे कानून लागू होते हैं, लेकिन सिविल मामलों में अलग-अलग कानून हैं। इसी दोहरापन को समाप्त करने को लेकर बात चल रही है।

आजाद जनता पार्टी लड़ेगी 90 सीटों पर चुनाव

रायपुर। आजाद जनता पार्टी का प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार हुई जिसमें तय किया गया कि पार्टी पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रत्याशी उतारेगी और 15 अगस्त 2023 को पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगा जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया और उसकी तैयारी के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

पार्टी के अध्यक्ष अमनदीप सिंह गिल ने बताया कि केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा चिकित्सा समेत कई सवाल किये जिसमें देश मे महंगाई कब कम होगी, देश मे बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, छत्तीसगढ़ में सभी माताओं को 500 रुपये महीना कब मिलेगा, 4 गैस सिलेंडर फ्री कब मिलेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कब कम करेंगे, बेगुनाह आदिवासियों पर अत्याचार कब बन्द होगा, चिटफंड का पैसा कब मिलेगा, पत्रकार सुरक्षा कानून व वकील सुरक्षा कानून पूर्ण रूप से कब लागू होंगे, भ्रष्टाचारियों को कब तक बचाते रहेंगे, झूठे केस बना कर लोगों को कब तक जेल भेज कर प्रताड़ित करेंगे, व्हीआईपी प्रथा कब बन्द करेंगे तथा उन्नत शिक्षा व उन्नत स्वास्थ्य जनता के लिए कब फ्री करेंगे यह बताएं। इन्हीं सब मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से आजाद जनता पार्टी पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी व 15 अगस्त 2023 को पार्टी का जन घोषणा पत्र जारी किया जाएगा जिसका कार्य आज से ही शुरू हो गया है। 100 से अधिक महिलाओं व पुरुषों ने आजाद जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

घोषणा पत्र निर्माण के लिए एक समिति की गठन किया गया जिसमें अमनदीप सिंह गिल अध्यक्ष, एडव्होकेट अभिषेक अमीन उपाध्यक्ष, संजीव मिश्रा, अमानत अली खान, करम लाल साहू, एडव्होकेट भागीरथी रात्रे, एडव्होकेट जानू खरे, एडव्होकेट आशीष जेठानी, पवन कुमार तिवारी, सौरभ यदु, श्रीमती विभा गुप्ता, प्रवीण पुरैना व डॉक्टर इमरान हिंगोरा को सदस्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने ग्राम भरदा में माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क का किया लोकार्पण

■ **मां को याद कर भावुक हुए मुख्यमंत्री, मंच पर नम हुई आंखें**

बालोद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बालोद जिले के ग्राम भरदा (टटेंगा) में स्वर्गीय माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण किया तथा माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित अतिथियों ने पार्क में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन के दौरान बिंदेश्वरी पार्क के सौंदर्यीकरण एवं पार्क में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपये की घोषणा की। इसी तरह उन्होंने खरखरा नदी से मेन रोड टटेंगा तक 03.50 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टटेंगा के उन्नयन की घोषणा की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, संसदीय सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो गए। मंच पर खड़े होकर बार-बार अपनी नजरों को यहां-वहां घुमाते रहे। कभी मंच से पीछे मुड़कर देखते। जितना बोलते, उससे ज्यादा शांत रहते। उनकी आंखें भर आईं। फिर खुद को संभाला और कहा कि, मां को जब भी याद करता हूं तो कुछ बोल नहीं पता। मां ने काफी कुछ सिखाया है। जब भी बोलना चाहता हूं आंखें और गला सब भर आता है। मुख्यमंत्री बघेल सोमवार को बालोद में मां स्वर्गीय बिंदेश्वरी देवी बघेल के नाम से बने पार्क का उद्घाटन करने और उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे।

जिले के देवरी ब्लॉक के ग्राम भरदा में सोमवार को कार्यक्रम था। इस दौरान सीएम ने पार्क का उद्घाटन और उनकी मां की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उद्यान के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने केवल 20 लाख रुपये उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए मांगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कलेक्टर काफी सक्रिय हैं और वह बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा की जगह मिली है तो लगना चाहिए। इस जगह पर भवन भी बने। जिससे शादी पार्टी का आयोजन के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर गार्डन बने। इसलिए उन्होंने एक करोड रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, पौने पांच साल का हमारा कार्यकाल रहा। दो साल तक कोरोना ने परेशान किया। हाथ बांध कर रह गए, लेकिन हमने सब के लिए काफी कुछ किया। आने वाले तीन महीने में आचार संहिता लग जाएगी। कहा जब प्रदेश का गठन हुआ तो कांग्रेस की एक महा बैठक हुई। उसमें उन्होंने 200 रुपये क्विंटल धान खरीदी का सुझाव दिया। फिर कांग्रेस ने घोषणापत्र में 250 रुपये बोनस शामिल किया। इसके बाद रमन सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने 270 रुपये कर दिया और झूठ कहा कि भाजपा ने शुरू किया है। रमन सिंह ने 15 क्विंटल किया और अब हमने 20 क्विंटल किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसान सफल और उन्नत है। रकबा बढ़ा है। अब 20 क्विंटल के हिसाब से 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। बजट और बढ़ेगा। यहां केंद्रीय मंत्री आते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं। मैं परेशान हूं। भाजपा ने किसानों को परेशान करने का काम किया है। आदिवासियों की जमीनें छीनने का काम किया है। सीएम ने कहा कि, जिस रेल लाइन का रेलमंत्री ने उद्घाटन किया, उसका मोदी जी फिर कर गए। जिस सड़क पर छह महीने से चलना शुरू हो गया, उसका उद्घाटन किया है। मोदी जी ने भी झूठ की पराकाष्ठा की। अमित शाह भी झूठ बोलने से बाज नहीं आए। सीएम भूपेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यहां पर पीएससी में हमने भर्तियां शुरू की। उस पर जबरदस्ती धांधली की बात कहकर आरोप लगाए और लोगों को बरगलाने का काम किया।

राज्यपाल ने सपरिवार श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर पूजा-अर्चना की

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन ने ओडिशा प्रवास के दौरान पुरी स्थित श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश एवं प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। उनके साथ राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित थीं।उन्होंने साक्षीगोपाल में पंचसखाओं को पुष्पांजलि अर्पित की। ओड़ीसा के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक और लेखक उत्कलमणि पंडित गोपाधुं दास, पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदाबरीश मिश्र, पंडित कृपासिंधु मिश्र एवं आचार्य हरिहर दास पंचसखा के नाम से जाने जाते हैं।

धान खरीदी पर सियासी जंग

प्रधानमंत्री ने 64 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदाः सुनील सोनी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धान खरादी वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है. सोनी ने कहा कि बीजेपी श्रेय नहीं ले रही है. प्रधानमंत्री ने सभी राज्य के साथ एक नीति अपनाया है. यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 64 लाख मीट्रिक टन चावल का एक-एक दाना खरीदा. उसी का परिणाम है, मुख्यमंत्री बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं.सांसद सोनी ने कहा कि चुनाव के कगार पर खड़े हैं तो 3 महीने पहले आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं.साढ़े 4 साल तक धान की नीति को बदलने का काम नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी ने दो बार रूस्क बढ़ाया. 2183 रुपए एमएसपी हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख मीट्रिक टन से कम धान खरीदते तो सड़क पर कपड़े फाड़ना चालू कर देते हैं, लेकिन मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों का ध्यान रखकर चावल खरीदा.वहीं स्वामी आत्मानंन्द स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि आत्मानंद स्कूल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ना सरकार के पास न शिक्षक हैं, ना स्कूल हैं न कमरे हैं ना व्यवस्थित वातावरण है. सरकार ने विज्ञापन जारी किया है कि अंग्रेजी माध्यम में पीएचडी की हो तो शिक्षक बनाएंगे.

सुनील सोनी ने कहा कि अंग्रेजी का ज्ञानी आदमी भी नहीं पढ़ा पाएगा, जब तक 2 से 3 साल का अनुभव न हो, जब तक इन बातों पर ध्यान नहीं देगा सब बर्बाद हो जाएगा. स्टूडेंट्स का जीवन बर्बाद कर रहे हैं. जो विधायक डिमांड करता है, तो स्कूल खोल देते हैं, पर आपके पास है क्या ? ये इस काल का सबसे बड़ा अपराध है.वहीं श्वष्ठ की कार्रवाई को लेकर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से मुख्यमंत्री तिलमिला रहे हैं, अधिकारी के ऊपर कारवाई होती है तो तिलमिलाते हैं, इतनी करोड़ की संपत्ति जब्त होकर नीलाम होने वाली है. आने वाला समय पता लगेगा,राजनीतिक चश्मे से श्वष्ठ नहीं देखते हैं, श्वष्ठ एक एजेंसी है, जो स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वतंत्र किया है. उससे कहा है कि देश को लूटने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर पैसा निकालें और जेल भेजें.सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकार शराब माफियाओं की संरक्षक है और उनके संरक्षक होने के कारण ही दो हजार करोड़ का घोटाला सामने आया है. श्वष्ठ का छापा यह सब रोकने के लिए है. आने वाले समय में बड़े घोटाले में फंसने वाले हैं. रक्षा कवच के रूप में कानून का सहारा लेकर नौटंकी कर रहे हैं.वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ियावाद पर बयान दिया है. सांसद सोनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में गांव के किसान, माताएं, बहनें सब परेशान हैं. सरकार ने नगर पंचायत के अंदर 1 रुपये नहीं दिया. गांव से लेकर शहर तक ऐसा कोई काम नहीं किया.बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकार ने केवल भ्रम फैलाया. आदिकाल से हमारी परंपरा संस्कृति रही है, उसी को उठाकर एक एजेंडा बनाकर छत्तीसगढ़ियावाद चलाने का भ्रम फैलाया है. केवल लूटने का काम किया. सरकार गुमराह कर रही है।

मेरी बात ✍ गिरीश पंकज

याद आई हार की जीत कहानी

महान कथाकार सुदर्शन की अमर कहानी है हार की जीत, जिसमें डाकू खड़ग सिंह अपाहिज बन कर धोखे से बाबा भारती से उन,के घोड़े सुल्तान को छीन कर ले जाता है। बाबा रास्ते में एक अपाहिज भिखारी को देखते हैं, तो उसके आग्रह पर उसे अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही अपाहिज बना खडग सिंह घोड़े पर बैठता है, तो उसके बाद वह घोड़े की लगाम छीन कर भाग खड़ा होता है। तब बाबा उसे आवाज़ दे कर रोकते हैं और कहते हैं, इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। लोगों की इस घटना के बारे में पता चल गया, तो लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती की बात खड्ग सिंह को लग गई। दूसरे दिन वह घोड़ा लेकर बाबा के पास आता है और उनके घोड़े को चुपचाप उनके अस्तबल में बांध कर निकल जाता है। उस वक्त उसकी आँखों में नेकी के आँसू थे। सुबह अपने घोड़े को पाकर बाबा प्रसन्न हो कर कह उठते हैं, अब कोई गरीब की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। इस कहानी को मैं आलोक मौर्य और योति मौर्य के घटना क्रम से जोड़कर देखता हूँ। आलोक सफाई कर्मी है, उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया , अछी कोचिंग दिलवाई तो योति पीएससी की परीक्षा पास करके एसडीएम बन गई।लेकिन उसके बाद योति बदल गई। उसका किसी अन्य अधिकारी से प्रेम हो गया। फिर उसने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए तेरह साल बाद दहेज का मामला दर्ज करवा दिया। उसका पति रोते बिलखते घूम रहा है और पत्नी की बेवफाई के बारे में सबको बता रहा है। आश्चर्य है कि वर्षो तक आलोक की पत्नी को पति के सफाईकर्मी होने के बारे में पता नहीं चला। जब वह एसडीएम बन गई, तब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पति ने झूठ बोला था। कमाल है पति सफाईकर्मी है, इसका मतलब यह तो नहीं कि पढ़ी-लिखी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध कायम कर ले, जो पहले से ही शादीशुदा है। अगर पति पसंद नहीं तो तलाक ले लेना था। किसी अन्य मर्द से अवैध संबंध क्यों बनाना ? यह भारत है, यहां इस तरह की अपसंस्कृति को समाज मान्यता नहीं देता। विदेश में शायद यह जायज हो। अलोक और योति मौर्य काण्ड के बाद दो मामले और सामने आए जिसमें पतियों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाया-लिखाया और जैसे ही पत्नी की नौकरी लगी, पत्नियों ने उनसे दूरी बढ़ा ली। नतीजा सामने है। अब तो अनेक पति अपनी पत्नियों को आगे पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी पत्नियाँ भी कहीं अंत में योति मौर्य न साबित हो जाएं। अगर योति मौर्य डाकू खड्ग सिंह की तरह उदारता दिखती और पति के साथ किसी तरह निर्वाह करके बनी रहती या चुपचाप तलाक ले लेती तो मामला उतना बड़ा नहीं बनता। लेकिन अब हर उस पति के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि कहीं एक दिन उनकी हालत भी आलोक मौर्य जैसी न हो जाए। किसी भी सामाजिक घटना का समाज में रह रहे लोगों की मानसिकता पर असर पड़ता है। अगर योति नैतिकता दिखती और खड्ग सिंह की तरह नैतिकता का घोड़ा बाबा भारती रूपी आलोक मौर्य के आंगन में बाँधे रखती, तो आज जो विवाद सार्वजनिक हो गया है, वह नहीं होता। लेकिन अब नैतिकता है एक किताबी शब्द बन कर रह गया है। वह शब्दकोश की शोभा है बस! यह मौका पाकर धोखा देने का क्रूर समय है. योति मौर्य ने यही किया। उसके अश्लील चैट, कॉल उसके क्रूर और पतित चरित्र को बताने के लिए पर्याप्त है लेकिन मज़े की बात, अनेक मॉड औरतें योति के पक्ष में हैं।यह पक्षधरता बता रही हैं कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, या जा चुका है. मगर यह सन्तोष की बात है कि असामाजिक मूल्य अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं क्योंकि अनेक औरतें योति की निंदा भी कर रही हैं।

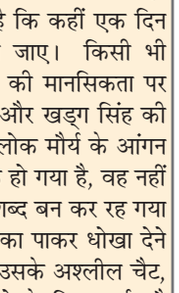

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का पलटवार

2019 से 2023 के बीच 2161 करोड़ का घोटाला : रमन सिंह

रायपुर। पीएम नरेंद्र मोदी की रायपुर में सभा के बाद से ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर आज रविवार को पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस पर सीएम भूपेश बघेल ने जो कल बयान दिया है। उनकी आपत्ति बड़ी अजीबो गरीब है। पीएम ने चुनावी सभा में कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। इस पर भूपेश बघेल क्यों घबरा रहे हैं, प्रधानमंत्री का इशारा भ्रष्टाचारियों पर है। साल 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, तब से भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है।

उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है, तो भूपेश बघेल सामने आते हैं। जब कोयला घोटाला, शराब घोटाला के मामले में जब प्रकरण बनते हैं, कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। यह तो कार्रवाई होगी ही और हो रही है। इसमें सीएम भूपेश बघेल को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही लक्ष्य बनाया है। वर्ष 2018 के बाद सीएम भूपेश बघेल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि डॉ. रमन सिंह की संपत्ति बढ़ी है। हर बार प्रेस में उनका यह बयान आता है, मुझे लगता है कि बघेल की याददाश्त कमजोर होती जा रही है।

रमन ने कहा कि बिलासपुर के हाईकोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। 2018 के बाद वह लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं। न्यायालय का फैसला क्या आया, इसके बाद भी सीएम भूपेश रिपीट पर रिपीट कर रहे हैं। यानी उच्च न्यायालय पर भी सीएम भूपेश बघेल को भरोसा नहीं है। जबकि उच्च न्यायालय स्पष्टतौर पर कहा है कि यह आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

रमन ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सीएम बघेल 2018 से वही राग अलाप रहे हैं। हर महीने प्रेस में मेरे संपत्ति के बारे में बात करते हैं। चुनाव आयोग इसका हिसाब लेता है। 2003, 2008 और 2013 का सभी जांच करने के बाद चुनाव आयोग ने इसमें कोई कमी नहीं पाई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी सीएम भूल नहीं पाते हैं। यह सीएम भूपेश की आदत का हिस्सा हो चुकी है।

जनचौपाल में आए 60 आवेदन, कलेक्टर ने निराकरण के दिए निर्देश

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभाकक्ष में आयोजित जनचौपाल में आमजनों की समस्याएं सुनी। जनचौपाल में 60 आवेदन आए इसपर कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री बी.बी पंचभाई, एसडीएम श्री देवेन्द्र पटेल उपस्थित थे। जनचौपाल में शिवाजी नगर, दलदल सिवनी वार्ड क्रमांक-7 के रहवासियों ने शासकीय भूमि में बच्चों के खेलनें के लिए गार्डन तथा बुजुर्गों को बैठने और सुख-दुख के कार्य के लिए भवन निर्माण कराने आवेदन दिया।

श्री मनीष सेन ने ओम हॉस्पिटल एवं सरस्वती नर्सिंग होम के चिकित्सक के विरूद्ध शिकायत करते हुए जांच करने का आग्रह किया। श्री सेन ने बताया कि उनके द्वारा उनकी पत्नी के ईलाज मे लापरवाही करने के संबंध में पूर्व में सीएचएमओ रायपुर को आवेदन दिया गया था, जिसपर जांच प्रतिवेदन भी तैयार किया गया था। मगर अभी तक कोई ठोस कदम नही उठाया जा सका है। श्री सेन ने आवश्यक कार्रवाई करने का निवेदन किया है।

शराब घोटाले में आबकारी मंत्री इस्तीफा दें: गुप्ता

रायपुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में आबकारी मंत्री का चुप रहना यह बताता है कि उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि आबकारी मंत्री का इस्तीफा लें या वे बताए कि उन्हें संरक्षण क्यों दे रहे है। एक गुट जहां भूपेश बघेल को पसंद कर रहा है तो दूसरा गुट टीएस सिंहदेव को,गुटबाजी से घिरी कांग्रेस पार्टी के लिए सोंच रही है आम जनता के लिए नहीं।

गुप्ता ने कहा कि ईडी ने शराब घोटाले मामले में 15 पन्ने में 2 हजार करोड़ के घोटाले की सूची तैयार कर कोर्ट में जमा किया है। इस मामले में सरकार के जितने भी अधिकारी व व्यापारी इस घोटाले से जुड़े हुए है वह सब अब जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि कोर्ट ने भी माना है कि इन लोगों ने अपराध किया है। बार-बार जमानत की अर्जी देने के बावजूद भी उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। इस मामले में अभी तक आबकारी मंत्री का न तो कोई बयान आया है और न ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उन्हे संरक्षण प्राप्त है।गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि टी.एस. सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाने का कारण कांग्रेस में चल रही अंदरुणी गुटबाजी को दूर करने का प्रयास है। टीएस सिंहदेव ने घोषणा समिति से हटने का फैसला ले लिया है, पहले यह कहा जा रहा था कि जय और वीरु की जोड़ी कभी टूटेगी नहीं। इससे पहले टीएस ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा दे चुके है जब ग्रामीणों के आवास उनकी सरकार नहीं बना रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से पूरा पैसा छत्तीसगढ़ को मकान बनाने के लिए भेज दिया था लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस पर रोक लगाए बैठे हुए थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

लोकतंत्र को बचाने प्रदेश में मौन सत्याग्रह : मरकाम

रायपुर। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद 12 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश में लोकतंत्र सत्याग्रह करेगी इस दिन कांग्रेसी मौन व्रत रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला निराशाजनक जरूर है, मगर अप्रत्याशित नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राहुल गांधी सत्य की राह के निडर यात्री हैं और वो भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि अंत में न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा। सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े, मोदी सरकार के निगरानी में जनता के पैसे लेकर, संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। भाजपा ने उनको तो आज़ाद कर दिया, पर झूठ की चालें चल, एक राजनैतिक साज़िश के तहत, राहुल गांधी को कठघरे में खड़ा कर, संसद से निलंबित करा दिया। भाजपा के राज में पहले भ्रष्टाचारी बाहर भागते हैं, और दूसरी तरफ़ मोदी जी की पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपित लोगों को भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन में धोकर, सत्ता हथियाने का खेल खेलती हैं। देश अब मोदी जी की भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति बड़ी गहराई से जान चुका है।

किसानों को गुमराह कर रही भूपेश सरकारः चंदेल

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने धान खरीदी को लेकर कहा कि, भूपेश बघेल सरकार किसानों को लगातार गुमराह कर ही है। धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। जबकि इनके तात्कालिक कृषि मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि मोदी सकार ने धान खरीदी के लिए 51563 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने सिर्फ 11048 करोड़ लगाए। इससे पता चलता है कि 40 हजार करोड़ ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार ने दिए हैं। कहा कि, भूपेश जी, विधानसभा के आंकड़ों को झूठा बता रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा कि, केंद्र सरकार राज्य से 80 फीसदी धान ही नहीं लेती, बल्कि धान के भुगतान का तीन चौथाई हिस्सा भी देती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्री किसानों से झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कहा कि, भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से सौतेला व्यवहार कर रही है। जिन किसानों ने कर्जा लिया, उनका माफ नहीं हुआ। दो साल का बोनस देने की बात जन घोषणा पत्र में कही थी, लेकिन नहीं मिला। प्रदेश के 18 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं, लेकिन राज्य सरकार को इस बात की परवाह नहीं। नारायण चंदेल ने कहा कि, पौने पांच सालों में केंद्र सरकार ने सभी मदों में आज तक दो लाख करोड़ रुपये भूपेश सरकार को दिए हैं।

भाजयुमो ने डीईओ ऑफिस का किया घेराव

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया. भाजयुमो ने स्कूल गेम्स में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान ष्ठश्वह्र को ज्ञापन भी सौंपा गया.भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश खेल एवं कला के प्रमुख अमन यादव ने कहा स्कूल के जो शिक्षा विभाग द्वारा खेल आयोजित किया जाता है. जिसका नोटिस 2 दिन पहले आता है. और तुरंत 2 दिन बाद ब्लॉक स्तर पर गेम कराया जाता है. उसके बाद जिला स्तर का गेम कराया जाता है. कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ ओलंपिक में भूपेश सरकार माहौल बनाने के लिए बच्चे जो स्कूल गेम साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं.उनका भविष्य अंधकार में रखा जा रहा है. स्कूल बच्चे का बोनस अंक राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है. बच्चों को इसमें बोनस मिलता है और छत्तीसगढ़ में जो गेम होता है वह ओलंपिक तक होता है. इसमें खिलाड़ी को लगातार परेशानी रही है. खिलाड़ियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. जूनियर खिलाड़ी के हाल बेहाल है. सीनियर युवा खिलाड़ी को अबतक राज्य अलंकरण नहीं दिया गया. जिसको लेकर आज युवा मोर्चा ने जिला शिक्षा अधिकारी को खेल के समय अवधि बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है.वहीं स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी आर.एल ठाकुर ने कहा किस्कूल खेल में गड़बड़ी मामल नहीं है. संचनालय से पत्र जारी हुआ था।

वादाखिलाफी करना कांग्रेस के डीएनए में ही हैः कौशिक

रायपुर। प्रदेश की कांग्रेस सरकार सत्ता पाने के लिए प्रदेश के हर वर्गों को धोखे में रखकर एवं पवित्र गंगाजल की झूठी कसम खाकर सत्ता में आई है। प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी का खामियाजा प्रदेश की जनता बेवजह भुगत रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेशभर की विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। कर्मचारी संगठनों की मांग जायज है क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने किए वादों के अनुसार अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की हड़ताल में चले जाने से प्रदेश की जनता पूरी तरह परेशान है। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के कारण छत्तीसगढ़ आज हड़तालगढ़ बन गया है।कौशिक ने कहा कि वादाखिलाफी करना कांग्रेस की डीएनए में ही है। चुनाव जीतने के बाद 10 दिनों में कर्जा माफ करने का वादा करने वाली कांग्रेस ने न तो पूरा कर्जा माफ किया नाही किसानों को पिछले 3 वर्षों का धान का बोनस दिया। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते देने का वादा करके बेरोजगारी भत्ता देने में भी बेतुके नियम बनाएं ताकि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता ना मिल सके। ठीक इसी तरह कर्मचारियों का डीए एवं एचआरए में केंद्र सरकार की तरह नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण कर्मचारी संगठन हड़ताल करने को विवश हो गए हैं।

93 फीसदी धान खरीदी में केंद्र सरकार देती है पैसाः चौधरी

रायपुर। बीजेपी ने धान खरीदी मामले में कांग्रेस की भूपेश सरकार पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार झूठ बोल रही है। धान खरीदने में सबसे बड़ा योगदान केंद्र सरकार की है। इसके बाद भी सरकार अनर्गल बातें कर रही है। बेबुनिबयाद आरोप मढ़ रही है। इस दौरान ओपी चौधरी ने धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से तुलनात्मक ब्यौरा पेश कर राज्य सरकार को घेरा। धान घरीदी को लेकर राज्य सरकार के आंकड़े पर जमकर बरसे। सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए उन्हें ठगेश बघेल कहा। ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 93 फीसदी धान खरीदी में केंद्र सरकार पैसा देती है। कांग्रेस सरकार नहीं। इसके बाद भी जानबूझकर कांग्रेस झूठ बोल रही है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का एक वीडियो भी दिखाया। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और बीजेपी के किसान नेता संदीप शर्मा ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में राज्य सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसमें बताना चाहिए कि प्रदेश सरकार ने कितना धान खरीदा है। इसके साथ ही जो धान खरीदा वो कहां रखा है।

जी-20 की बैठकों की व्यवस्था की तैयारियां शुरू, मुख्य सचिव ने ली बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18-19 सितम्बर 2023 को जी-20 देशों के कार्यसमूह की बैठक का आयोजित होगी। बैठकों की तमाम व्यवस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने संस्कृति, नगरीय प्रशासन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवा रायपुर में एयरपोर्ट से मेयफेयर रिसार्ट एवं नवा रायपुर के अन्य मार्गों की वर्तमान स्थिति एवं आयोजन हेतु निर्मित होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर थ्री-3डी वॉक-थ्रू के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने नवा रायपुर के विभिन्न मार्गों पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने वाले स्थल, पुरातात्विक नगरी सिरपुर, चित्रकोट जलप्रपात, वन एवं खनिज संपदा और औद्योगिक विकास सहित छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी संबंधी होर्डिंग्स इत्यादि लगाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को एयरपोर्ट से मेफेयर रिसार्ट सड़क मार्ग, पुराना जी.ई. रोड, व्हीआईपी एवं अन्य मार्गों का सौन्दर्यीकरण और साज-सज्जा के एवं अन्य आवश्यक कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए है। संस्कृति विभाग के अधिकारियों को जी-20 की बैठकों में आने वाले विदेशी डेलीगेट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, संगीत और संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करने के लिए अभी से आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल करने के निर्देश दिए है। अंतिम रिहर्सल मुख्य मंच स्थल पर करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि अंतिम रिहर्सल सुरक्षा अधिग्रहण के पूर्व कर ली जाए। इसी तरह से जी-20 वाटिका हेतु उपयुक्त स्थलों पर विदेशी आगन्तुकों द्वारा पौधारोपण कराए जाने की तैयारी करने के निर्देश दिए। बैठक में व्यवस्थाओं की विभिन्न तैयारियों के संबंध में नगर निगम रायपुर, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण और संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में संस्कृति विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., संचालक श्री विवेक आचार्य, आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री मयंक चतुर्वेदी, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री किरण कौशल सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

सीएम हाउस के गेट पर रख दी कॉपी-किताबें

■ महासमुंद से आए छात्र-छात्राओं ने कहा- हमें टीचर चाहिए, हड़बड़ाए अधिकारियों ने तत्काल नियुक्ति का वादा किया

रायपुर। स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स की कमी की शिकायत लेकर महासमुंद जिले के अमलोर हाई स्कूल के छात्र सीएम हाउस तक पहुंच गए। रायपुर के सिविल लाइंस स्थित ष्टरूहाउस के गेट पर कॉपी-किताब और बैग रखकर स्टूडेंट्स ने शिक्षकों की मांग की। वहीं सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया की शाम तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। जिसके बाद बच्चे महासमुंद वापस लौट गए।

जानकारी के मुताबिक महासमुंद जिले के शिवपुर ब्लाक में अमलोर गांव के कुछ ग्रामीण और स्कूली बच्चे आज सुबह-सुबह रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। वे जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते है वहां सिर्फ एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। तमाम स्कूलों में बच्चों के बैठने से लेकर पेयजल तक की व्यवस्था तक नहीं हैं। यहां तक की एक स्कूल महज शिक्षामित्र के सहारे चल रहा है। पढ़ाई का जिम्मा और स्कूल की व्यवस्था यहां एक ही शिक्षक के सहारे टिकी है।स्टाफ न होने की वजह से दो-दो कक्षाओं के बच्चों को एक कमरे में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। वहीं सरकार ने बच्चों की परेशानी को देखते हुए उन्हें आश्वासन दिया है। शिक्षा विभाग से जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी।यहां पहुंचे छात्रों का कहना है शिक्षक नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.